www.hindmatamirror.com • वर्ष: 12 • अंक: 269 • ठाणे, शुक्रवार 3 जुलाई, 2026 • पेज: 8 • मूल्य: 2 रुपए hindmatamirror1@gmail.com

दैनिक ठाणे

हिंदमाता मिरर

RNI. NO. MAHHIN/2011/43060

पैनी नजर, पुख्ता खबर

विराट कोहली कर रहे पूर्व भारतीय कोच के साथ ट्रेनिंग

पेज 8

शाहरुख ने विदेश में बनवाया खुद का क्रिकेट स्टेडियम

8 पेज

सुप्रभात

स्त्रियों की अवस्था में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं। पक्षी का एक पंख के सहारे उड़ना नितांत असंभव है। - **विवेकानंद**

मौसम का मिजाज

सूर्यास्त (3 जुलाई) 7:20 बजे, सूर्योदय (4 जुलाई) 6:05 बजे, **तापमानः 27 डिग्री से. (गरज के साथ बौछार।)**

शरद पवार के 8 सांसदों पर शाह की नजर!

मानसून सत्र के पहले एनडीए का मिशन दो तिहाई बहुमत

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इससे पहले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) दो तिहाई बहुमत जुटाने की जुगत में जुटा हुआ है। पहले तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों के पाला बदल और फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने के बाद अब एनडीए की नजर शिवसेना (यूबीटी) की गठबंधन सहयोगी शरद पवार की पार्टी के सांसदों पर है।

सूत्रों की मानें तो एनसीपी (शरद पवार) के लोकसभा में आठ सांसद एनडीए के संपर्क में हैं। हालांकि इसे लेकर अभी कुछ भी तय नहीं है कि इस सांसदों का ठिकाना कौन सी पार्टी होगी। एनडीए की अगुवाई कर रही भाजपा इन सांसदों को लेने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी नेतृत्व ने इनमें से किसी को मंत्री पद देने के कयास भी खारिज कर दिए हैं। शरद पवार की पार्टी के सांसद भविष्य में सुनेत्रा परिवार की अगुवाई वाली एनसीपी में जा सकते हैं। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की संभावनाएं फिलहाल नकारी जा रही हैं। एनसीपी (शरद पवार) के सांसदों की बगावत के पीछे पार्टी के कांग्रेस में विलय के कयासों को वजह बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में विलय की अटकलों से शरद पवार की पार्टी के सांसदों में बेचैनी है। इस पूरी कवायद के पीछे महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कराने के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिशें हैं।

शरद पवार के सांसद भी विकास के भूखे!

शरद पवार की पार्टी के सांसद 2029 के लोकसभा चुनाव में अपने टिकट को लेकर सशंकित हैं। एनसीपी (एसपी) के कुछ सांसदों का यह भी कहना है कि केंद्र में एनडीए की सरकार है ही, महाराष्ट्र में भी एनडीए ही सत्ता में है। ऐसे में उनको अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कराने, विकास कार्य कराने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

ट्रेन की चपेट में आई महिला की मौके पर मौत

इस साल अब तक 93 लोगों की जा चुकी है जान

मयंक रावत @ विरार

वैतरणा और विरार रेलवे स्टेशनों के बीच गुरुवार सुबह एक दर्दनाक रेल हादसे में अज्ञात महिला की मौत हो गई। नारंगी रेलवे फाटक के पास वलसाड-मुंबई सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद कुछ समय तक ट्रेन घटनास्थल पर खड़ी रही, जिससे मुंबई की ओर जाने वाली रेल सेवाएं प्रभावित हो गईं। जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे वलसाड-मुंबई सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन विरार की ओर आ रही थी। इसी दौरान नारंगी रेलवे फाटक के समीप एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी तेज थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोको पायलट ने तत्काल ट्रेन रोक दी और रेलवे कंट्रोल को सूचना दी। सूचना पाते ही रेलवे पुलिस और संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

इस साल 93 लोगों की जा चुकी है जान

रेलवे पुलिस के अनुसार, मीरा रोड से वैतरणा रेलखंड के बीच वर्ष 2026 में अब तक रेल हादसों में 93 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकांश दुर्घटनाएं रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुई हैं। रेलवे पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए रेलवे ट्रैक पार करने से बचें और केवल फुटओवर ब्रिज या अधिकृत मार्ग का ही उपयोग करें। इससे ऐसे हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है।

कहीं खुले पड़े हैं मैनहोल... कहीं पानी में दौड़ रहा है जानलेवा करंट... कहीं पेड़ गिरने को तैयार...

बारिश मूसलाधार... मुंबईकर बन रहे शिकार

- प्रशासन ने कदम-कदम पर बिछा रखा है मौत का जाल... अपने दम पर घर से बाहर निकलें मुंबईकर
- 6 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी, मुंबई-ठाणे के लिए ऑरेंज, तो पालघर के लिए रेड अलर्ट

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

मुंबई में गुरुवार सुबह एक बार फिर तेज बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में जलभराव हो गया और सड़क व रेल यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई। वहीं, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिनभर बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान शहर के कई इलाकों में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। गुरुवार तड़के से जारी भारी बारिश के कारण दादर, परेल, हिंदमाता, चारकोप, वरली, गोरेगांव और अंधेरी जैसे प्रमुख इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा तथा वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई। पटरियों पर जलजमाव के कारण लोकल ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। रेल यात्रियों ने बताया कि कई लोकल ट्रेन निर्धारित समय से 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही हैं, जिससे सुबह के व्यस्त समय में स्टेशनों और ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई। भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने मुंबई और उसके उपनगरों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। साथ ही गुरुवार रात और शुक्रवार तड़के अत्यधिक भारी बारिश होने का भी अनुमान है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

कहीं रेड, तो कहीं ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, महाराष्ट्र से लेकर उत्तरी केरल तट तक एक मजबूत कम दबाव का क्षेत्र (लो-प्रेशर ट्रफ) सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से 6 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार से अत्यधिक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने पालघर और पुणे जिले के घाट क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चंद्रपुर जैसे प्रमुख जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों के निवासियों को बिना वजह घरों से बाहर न निकलने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर मुंबईकर बेहद सजग होकर रहें।

कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में आफत की बारिश

मौसम विभाग के अनुसार कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील हैं। 3 जुलाई को इन इलाकों में मूसलाधार बारिश की पूरी संभावना है, जबकि 4 से 6 जुलाई के दौरान बारिश की तीव्रता और अधिक बढ़ सकती है।

99 से अधिक पेड़ गिरे, शॉर्ट सर्किट के 13 मामले सामने आए

पिछले 24 घंटों से मुंबई में तेज हवाओं के साथ लगातार भारी बारिश हो रही है। इससे पूरे शहर का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अनुसार, पेड़ या उनकी शाखाएं गिरने की 99 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, शॉर्टसर्किट के करीब 13 मामले और दीवार गिरने व जलभराव की छह घटनाएं भी सामने आई हैं।

पालघर में स्कूल, कॉलेज बंद

गुरुवार को मुंबई और आसपास के जिलो में मॉनसून की भारी बारिश जारी रही, जिसके चलते पालघर जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी। आईएमडी के अपग्रेडेड रेड अलर्ट के बाद मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (एमएमआर) के अधिकारी हाईअलर्ट पर हैं।

'ऑपरेशन' करते नेता, दम तोड़ती जनता

शिवसेना और एनसीपी के विभाजन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति 'ऑपरेशन लोटस' से 'ऑपरेशन टाइगर' तक पहुंच चुकी है, लेकिन हर साल बारिश में बदहाल हो जानेवाली मुंबई की तस्वीर इतने सारे ऑपरेशनों के बाद भी नहीं बदली है। बीएमसी के प्रशासक राज के दौरान जब शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए मुंबई की सड़कों पर जहां-तहां रंग-बिरंगी विद्युत बल्बों की झालरें, तोरण इस तरह सजाए गए थे कि शहर किसी डिज्नीलैंड की तरह नजर आने लगा था। बीएमसी के तकरीब नब्बे हजार करोड़ के फिक्स्ड डिपॉजिट का सदुपयोग करने का हवाला देकर पुलों और पेड़ों तक को बिजली के तोरण से सजा दिया गया था। इसके बाद बीएमसी चुनाव हुए। प्रशासक राज खत्म हुआ। सीएम फडणवीस और डीसीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के हाथ में बीएमसी की सत्ता आई। लेकिन इस बार बारिश में तीन दिनों में ही मुंबईकरों का जो हाल बेहाल हुआ है, उससे यही प्रतीत होता है कि सरकार का सारा ध्यान सियासी ऑपरेशनों पर लगा हुआ है, जिसके चलते बीएमसी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से घनघोर लापरवाही बरती गई है। नालों की सफाई में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। मुंबई शहर में तो फिर भी थोड़ा-बहुत काम हुआ है, लेकिन उपनगरों में जलजमाव के जो हालात नजर आ रहे हैं उससे तो यही प्रतीत होता है कि नगर निगम प्रशासन, ठेकेदारों और क्षेत्र के पालक होने का दम भरनेवाले चौधरी नेताओं ने नाला सफाई की राशि अपनी जेब में डाल दी और नाला सफाई का ठेका पहली बारिश को दे दिया।

करोड़ों रुपए गए पानी में!

तुंगारेश्वर महादेव मार्ग पर चंद दिनों की बारिश में निकला 'पत्थर बोल्ट'!

बिपिन तिवारी @ वसई

वसई पूर्व स्थित प्रसिद्ध तुंगारेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों के लिए एक बड़ी चिंताजनक खबर सामने आ रही है। बप्पा सीताराम मंदिर से लेकर चकाचक महादेव मंदिर के पुल तक की सड़क का तो डामरीकरण (पिचिंग) कर दिया गया है, लेकिन उसके आगे की कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। पुल के आगे की सड़क का डामरीकरण नहीं किया गया, बल्कि उसे बिना डामर के ही तीन परतों (लेयर्स) में तैयार किया गया था, क्योंकि डामरीकरण को इजाजत वन विभाग द्वारा नहीं दी गई थी। अब बारिश में इस सड़क की असलियत सामने आने लगी है। ताजा स्थिति यह है कि बिना डामर वाली यह सड़क जगह-जगह कीचड़ से सन चुकी है, जिससे राहगीरों और वाहनों का गुजरना दूभर हो रहा है। इतना ही नहीं, पानी के तेज बहाव के कारण सड़क की ऊपरी परत बहती जा रही है, जिसके चलते सड़क के निर्माण में इस्तेमाल किए गए बड़े-बड़े पत्थर (बोल्ट) अब जगह जगह बाहर निकल आए हैं। बरसात के पानी के कारण सड़क कई जगहों से कटनी भी शुरू हो गई है। जब इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तब वसई-विरार की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसका श्रेय लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर तरफ अपनी पीठ थपथपाई जा रही थी। लेकिन अब श्रेय लेनेवाले सभी नेता-कार्यकर्ता नदारद हैं।

मुंबईकरों की जान खतरे में... मुंब्रा में लड़की की मौत

लगातार बारिश जानलेवा बन गई है। साकीनाका में असलम शेख नाले में बह गए। मुंब्रा के यास्मीन पार्क स्थित कादर पैलेस में भारी बारिश के दौरान जलभराव हो गया था। इसी इमारत की बी-विंग में रहने वाली 17 वर्षीय आलिया चांदीवाला किसी काम से घर के बाहर निकली थी। सड़क पर भरे पानी में बिजली का करंट उतरा हुआ था। जैसे ही आलिया ने उस पानी में कदम रखा, वह करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों और स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी तरह खारघर में एक 17 साल का लड़का तालाब में डूब गया। भिवंडी में बिजली का झटका लगने से एक 26 साल के व्यक्ति की मौत हो गई जबकि मुंबई के वालकेश्वर इलाके में एक इमारत का हिस्सा गिरने से 51 साल के एक व्यक्ति की जान चली गई। एक अन्य घटना में नवी मुंबई के कामोठे इलाके में एक इमारत की छत गिरने से 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। नवी मुंबई के नेरुल में पानी से भरे इलाके में बिजली के संपर्क में आने से दो लड़कियां घायल हो गईं। यह घटना भारी बारिश के दौरान बाढ़ और खुले बिजली के इन्फ्रास्ट्रक्चर से होने वाले खतरों को उजागर करती है।

साकीनाका में खुले मैनहोल में गिरकर 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत, चार अधिकारी निलंबित

साकीनाका इलाके में खैरानी रोड पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां खुले मैनहोल में गिरने से 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान असलम इसाक शेख के रूप में हुई है। बीएमसी ने इस मामले में चार अफसरों को निलंबित किया है। यह हादसा उस समय हुआ जब बृहन्मुंबई महानगरपालिका का सीवेज ऑपरेशन विभाग मैनहोल पर सुरक्षा जाली लगाने का काम कर रहा था। शुरुआती जानकारी के अनुसार, ठेकेदार की ओर से सुरक्षा के जरूरी इंतजाम नहीं किए गए थे, जिससे यह गंभीर लापरवाही सामने आई।

नहीं लगाए थे चेतावनी बोर्ड

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक काम के दौरान मैनहोल के चारों ओर न तो बैरिकेड लगाए गए थे और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था। इसी दौरान असलम शेख मोबाइल पर बात करते हुए वहां से गुजर रहे थे। बताया जा रहा है कि काम कर रहे कर्मचारियों ने उन्हें आवाज देकर रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वे संतुलन खो बैठे और सीधे खुले मैनहोल में गिर गए। घटना के बाद बीएमसी और मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

चार अधिकारियों पर गिरी गाज

घटना को गंभीरता से लेते हुए बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने तत्काल जांच के आदेश दिए और प्रारंभिक रूप से लापरवाही मानते हुए 'एल' विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर समेत चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में असिस्टेंट कमिश्नर धनाजी हेर्लेकर, असिस्टेंट इंजीनियर दीपक चौगुले, जूनियर इंजीनियर अभिजीत चौगुले और सीवेज ऑपरेशन के असिस्टेंट इंजीनियर उत्तम पाटील शामिल हैं।

मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

इसके साथ ही संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश भी दिए गए हैं। मामले की जांच के लिए अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगर) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है, जो 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। महापौर रितू तावडे ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

आठ दिनों में सेफ्टी ऑडिट

बीएमसी ने यह भी निर्देश दिया है कि अगले 8 दिनों में पूरे मुंबई के सभी मैनहोल की 100 प्रतिशत सुरक्षा जांच (सेफ्टी ऑडिट) की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। अधिकारियों के अनुसार, प्राथमिक जांच में साफ हुआ है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है।

मैनहोल में गिरने से व्यक्ति की मौत गैर-इरादतन हत्या के समान: महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुंबई में मैनहोल में गिरने से एक व्यक्ति की मौत को गुरुवार को गंभीर और गैर-इरादतन हत्या का मामला बताया। एक सदस्य की ओर से उठाए गए इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने राज्य सरकार को सदन की दिनभर की कार्यवाही समाप्त होने से पहले घटना के बारे में विस्तृत बयान देने के लिए कहा। भाजपा विधायक अमित साटम ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की मांग की। उन्होंने सरकार से केवल जांच के आदेश देने के बजाय तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। नार्वेकर ने मैनहोल के कारण हुई मौत को गंभीर मामला बताया और कहा कि यह गैर-इरादतन हत्या के समान है।

बिश्नोई गैंग की रंगदारी बेलगाम!

विधायक को जान से मारने की धमकी, मिलेगी वाई-प्लस सुरक्षा

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने बिश्नोई गैंग के गुर्गों को खोज निकालने और उन पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन बिश्नोई गैंग के रंगदारों पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान को बार-बार धमकी के अलावा जहां-तहां कारोबारियों को धमकाना लगातार जारी है। अब कांग्रेस विधायक साजिद पठान ने गुरुवार को दावा किया कि गैंगस्टर शुभम लोणकर ने उनके सहयोगी के साथ हाल ही में हुई बातचीत के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी दी। विधान भवन परिसर में पत्रकारों से अकोला के विधायक साजिद पठान ने कहा कि उनकी पार्टी के पार्षद और करीबी सहयोगी आकाश कवाले को हाल ही में लोणकर (लॉरेंस बिश्नोई गैंग का संदिग्ध सदस्य) का फोन आया था, जिसने कथित तौर पर विधायक को जान से मारने की धमकी दी। कावले को (फोन कॉल के दौरान) बताया गया कि पठान को मार दिया जाएगा और पूरा अकोला यह देखेगा। मुझे पहले भी ऐसी धमकी मिली थी और मैंने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था। मैंने मुख्यमंत्री को भी इसकी जानकारी दी थी। मुझे हैरानी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जाने वाले लोणकर के पास मेरा नंबर या मेरे करीबी पार्षद का नंबर कैसे हो सकता है।

वाई-प्लस सुरक्षा दी जाएगी: मंत्री

महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक साजिद पठान को गैंगस्टर शुभम लोणकर से रंगदारी की धमकी मिलने के बाद वाई-प्लस श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने इसकी जानकारी दी। विपक्षी दल की ओर से विधानमंडल में यह मुद्दा उठाए जाने के बाद गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधान परिषद में यह घोषणा की। वाई-प्लस श्रेणी की सुरक्षा में 11 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं।

गोल्ड स्मगलिंग गैंग के सात गुर्गे गिरफ्तार

34 करोड़ का 24 किलो सोना जब्त

हिंदमाता नेटवर्क @ कोलकाता

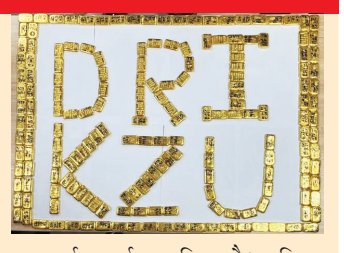

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने विदेश से सोने की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ संचालित एक सुव्यवस्थित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है। खुफिया जानकारी पर आधारित एक अभियान में, डीआरआई अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में कृष्णानगर से चकदाहा की ओर अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर यात्रा कर रहे सात व्यक्तियों को रोका।

बेल्ट में छिपा रखा था सोना

पकड़े गए व्यक्तियों की तलाशी लेने पर विदेशी चिह्न वाले और विकृत किए गए सोने के 180 बिस्कुट बरामद हुए, जिन्हें उन्होंने पहचान से बचने के लिए कमर पर विशेष रूप से सिलवाए गए कपड़े के बेल्ट के अंदर चतुराई से छिपा रखा था। लगभग 24 किलोग्राम वजन का और लगभग 34 करोड़ रुपए मूल्य का बरामद विदेश से तस्?करी किया गया सोना सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया।

सात लोग गिरफ्तार

तस्करी अभियान में शामिल सभी सात व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि वाहकों ने भारत-बांग्लादेश सीमा के पास के स्थानों से तस्करी किया हुआ सोना एकत्र किया था और इसे आगे वाहकों के एक अन्य समूह को सौंपने के लिए ले जा रहे थे।

महिला किसानों को मान्यता देने वाला विधेयक मंजूर

देश में अपनी तरह का पहला प्रस्तावित कानून

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

महाराष्ट्र विधानसभा ने गुरुवार को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया, जिसका उद्देश्य महिला किसानों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, संस्थागत ऋण, कृषि सेवाओं तथा महिला किसान पहचान पत्र तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना है। देश में अपनी तरह का पहला प्रस्तावित कानून माने जा रहे महिला किसान सशक्तीकरण विधेयक का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को औपचारिक मान्यता देना है। इसके तहत कृषि कार्यों से जुड़ी महिलाओं की सहायता के लिए एक विशेष कोष बनाया जाएगा तथा अकेली महिला कृषकों को विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक को अब विधान परिषद में पेश किया जाएगा।

कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर जोर

कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने कहा कि विधेयक में उल्लेख किया गया है कि बुवाई से लेकर कटाई तक खेती के हर चरण में पुरुषों के साथ काम करने और डेरी एवं पशुपालन जैसी सहायक कृषि गतिविधियों में भागीदारी के बावजूद, महिलाएं संस्थागत लाभों से काफी हद तक वंचित रही हैं, क्योंकि कृषि भूमि का पंजीकरण आमतौर पर परिवार के पुरुष सदस्यों के नाम पर होता है।

महिला किसान पहचान पत्र जारी करने का प्रावधान

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून में महिला किसान की व्यापक परिभाषा अपनाई गई है, जिसमें केवल फसल उत्पादन ही नहीं, बल्कि पशुपालन जैसी कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। भरणे ने कहा, विधेयक में महिला किसान पहचान पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से सुविधाएं मिलेंगी।

किसानों के मुद्दे पर बहिर्गमन

रंगदारी की धमकी और किसानों की आत्महत्या को लेकर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

महाराष्ट्र विधानसभा में गुरुवार को विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस विधायक साजिद पठान को गैंगस्टर शुभम लोनकर से रंगदारी की धमकी मिली है। उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बाद में, उन्होंने किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर चर्चा की मांग की और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा मांग अस्वीकार किए जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि पठान को बुधवार रात अमेरिका में रहने वाले गैंगस्टर शुभम लोनकर (जो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताया जाता है) से रंगदारी के लिए फोन आया। उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक दिन पहले सदन में कहा था कि देश के बाहर और अंदर से काम करने वाले गिरोहों को फलने-फूलने नहीं दिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का जवाब

मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही विधानसभा को भरोसा दिला चुके हैं कि सभी विधायकों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज कराएं, कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई ने विपक्ष से रंगदारी की धमकी से संबंधित फोन के बारे में पूरी जानकारी देने को कहा और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। साजिद पठान ने बताया कि जब उन्हें पहली बार धमकी मिली थी, तो मुख्यमंत्री ने उन्हें (उसी दिन) आधी रात के आसपास फोन किया, सुरक्षा का भरोसा दिलाया और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई। उन्होंने कहा कि लेकिन फिर से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि गिरोहों को खत्म कर दिया जाएगा और कुछ ही घंटों बाद मुझे रंगदारी के लिए फोन आता है। मैं धमकियों से डरता नहीं हूं।

अध्यक्ष का आश्वासन

इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए अध्यक्ष नार्वेकर ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि खतरे का आकलन करने के बाद उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

किसानों का मुद्दा

कांग्रेस सदस्य वडेट्टीवार और नाना पटोले ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विधानसभा के मॉनसून सत्र के बीच बुधवार को लातूर में दो किसानों ने आत्महत्या कर ली। वडेट्टीवार ने चर्चा की मांग करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान किसानों की मौत कृषि संकट की गंभीरता को दर्शाती है। उन्होंने सरकार से तत्काल जवाब की मांग की। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसानों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं, बढ़ते आर्थिक संकट और किसानों से जुड़े अनसुलझे मुद्दों पर सदन में तत्काल और विस्तृत चर्चा की जरूरत है।

विपक्ष का बहिर्गमन

विपक्ष के सदस्य किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर बोलना चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। विपक्ष ने किसानों की आत्महत्या के मुद्दे को सर्वाधिक प्राथमिकता वाला बताते हुए विरोध में सदन से बहिर्गमन किया। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा इस मामले पर चर्चा की अनुमति न दिए जाने की वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया।

हत्या की साजिश की पड़ताल

• साजिश वाले स्थान पर घटना से जुड़े सबूत भी किए बरामद

हिंदमाता नेटवर्क @ पुणे

महाराष्ट्र पुलिस गुरुवार सुबह सिया गोयल को पुणे के उस स्थान पर ले गई, जहां उसने और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर यह साजिश रची थी कि रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल को लोहागढ़ किले की पहाड़ी से नीचे कैसे धक्का देना है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

शादी से पहले वारदात

केतन अग्रवाल और सिया गोयल की शादी इसी वर्ष नवंबर में होने वाली थी। कथित हत्या के बाद पुलिस ने सिया और चेतन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों तीन जुलाई तक पुलिस हिरासत में हैं। पुणे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि सिया और चेतन ने लुल्लानगर स्थित एक क्लब के पास खुले स्थान पर यह साजिश रची थी कि केतन को लोहागढ़ किले की पहाड़ी से कैसे धक्का देना है। इसी सिलसिले में आज सिया को उस स्थान पर ले जाया गया।

घटना वाले दिन के कपड़े मिले

अधिकारी ने बताया कि सिया के घर की तलाशी के दौरान पुलिस ने वे कपड़े भी बरामद कर लिए, जिन्हें उसने घटना वाले दिन कथित तौर पर पहना था। पुलिस के अनुसार, सिया गोयल और चेतन चौधरी ने इसलिए केतन अग्रवाल की हत्या की, क्योंकि वह उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था। पुलिस बुधवार को सह-आरोपी चेतन चौधरी को भी घटनास्थल पर लेकर गई थी, जहां अपराध के घटनाक्रम को समझने के लिए दृश्यों का रूपांतरण किया।

कपड़े भी बरामद

पुलिस ने पुणे के मार्केट यार्ड इलाके में स्थित सिया गोयल के घर की तलाशी के दौरान वे कपड़े भी बरामद किए हैं, जिन्हें उसने 18 जून को घटना वाले दिन कथित तौर पर पहना था। सिया गोयल (20) और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी (22) पर आरोप है कि उन्होंने 18 जून को पुणे जिले के लोहागढ़ किले की पहाड़ी से केतन अग्रवाल (25) को धक्का देकर उसकी हत्या कर दी।

पहले भी कराया गया था घटनाक्रम

इससे पहले रविवार को पुलिस सिया को भी घटनास्थल पर ले गई थी। उस दौरान उसकी मौजूदगी में एक पुतले को खाई में धक्का देकर कथित घटनाक्रम को दोहराया गया था। पुलिस के अनुसार, केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने अपनी शिकायत में कहा था कि उनके बेटे ने कई बार सिया की चेतन चौधरी से बढ़ती नजदीकियों को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि सिया अक्सर अपनी बातचीत में चेतन का जिक्र किया करती थी।

नए आरटीआई नियम स्थगित, सरकार का फैसला

अन्ना हजारे के आंदोलन की चेतावनी के बाद सरकार ने नियमों पर लगाई रोक

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

महाराष्ट्र सूचना का अधिकार (आरटीआई) नियम, 2026 में आवेदन शुल्क बढ़ाने और पहचान का सबूत अनिवार्य करने जैसे कई बदलाव प्रस्तावित थे, लेकिन उसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के बाद स्थगित कर दिया गया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

हजारे का विरोध

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने नए नियमों का विरोध किया था और चेतावनी दी थी कि अगर आरटीआई नियमों में किये गये बदलाव वापस नहीं लिए गए, तो वह पांच जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। इन बदलावों में यह शर्त भी शामिल थी कि हर आवेदन में सिर्फ एक ही विषय होना चाहिए।

मुख्यमंत्री का निर्देश

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री फडणवीस ने आरटीआई के मुख्य आयुक्त से नए अधिसूचित नियम को स्थगित कर देने को कहा है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी और 12 जून को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, नए नियम प्रकाशन के साथ ही तुरंत लागू हो गए थे। नए नियमों के तहत, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी मांगने वाले आवेदकों को 30 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा।

जानकारी लेने का शुल्क

जानकारी के लिए शुल्क 'ए-फोर साइज' पृष्ठ के लिए पांच रुपए प्रति पेज और स्कैन किए गए या डिजिटल पेज के लिए पांच रुपए तय किया गया है, जबकि रिकॉर्ड देखने की सुविधा पहले घंटे के लिए मुफ्त होगी और उसके बाद प्रति घंटे 50 रुपए का शुल्क लगेगा। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को आवेदन शुल्क से छूट मिलेगी, हालांकि 50 पृष्ठ से ज्यादा जानकारी के लिए शुल्क देना होगा।

आवेदन की नई शर्तें

नियमों में यह भी कहा गया है कि आरटीआई आवेदन आम तौर पर एक ही विषय तक सीमित होना चाहिए और आमतौर पर 150 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कई विषय शामिल हैं, तो जन सूचना अधिकारी सिर्फ पहले विषय पर कार्रवाई कर सकता है और आवेदक को बाकी मुद्दों के लिए अलग-अलग आवेदन देने की सलाह दे सकता है।

पहचान पत्र अनिवार्य

एक और अहम बदलाव यह है कि आवेदकों को आरटीआई आवेदन के साथ भारतीय नागरिकता साबित करने वाले फोटो पहचान पत्र की खुद से प्रमाणित प्रति जमा करनी होगी। ऐसे सबूत के बिना दिये गये आवेदनों को जरूरी जानकारी पूरी करने के लिए वापस भेजा जा सकता है।

वेबसाइट से जानकारी

नियमों के अनुसार, अगर मांगी गई जानकारी सरकार या संबंधित सरकारी संस्था की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले से मौजूद है, तो जन सूचना अधिकारी आवेदक को उसकी कॉपी देने के बजाय उसे ऑनलाइन देखने के लिए कह सकता है। नियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आम तौर पर सार्वजनिक गतिविधि या जनहित से जुड़ी न होने वाली निजी जानकारी का खुलासा नहीं किया जाएगा, जब तक कि कोई बड़ा जनहित साबित न हो जाए।

नियम वापस लेने की मांग

हजारे ने सरकार से 'महाराष्ट्र सूचना का अधिकार नियम, 2026' को वापस लेने की मांग की थी। उनका आरोप था कि ये नियम आरटीआई कानून की मूल भावना को कमजोर करते हैं तथा नागरिकों के लिए जानकारी हासिल करना और मुश्किल बना देते हैं। हजारे ने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया था।

करोड़ों के कर्ज मामले में आवास डेवलपर्स को राहत

आवास डेवलपर्स के खिलाफ दायर याचिका खारिज

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को बड़ा झटका देते हुए आवास डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर दिवालियापन याचिका खारिज कर दी है। बैंक ने कंपनी पर 140 करोड़ रुपए से अधिक के बकाये का दावा करते हुए उसके खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी। एनसीएलटी ने आदेश में कहा कि बैंक की याचिका तय कानूनी समय सीमा के बाद दाखिल की गई थी, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मामला मूल रूप से पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक द्वारा आवास डेवलपर्स को दिए गए कर्ज से जुड़ा है। बाद में आरबीआई की मंजूरी से पीएमसी बैंक का विलय यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो गया था, जिसके बाद यह कर्ज यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के खाते में आ गया। बैंक के अनुसार वर्ष 2007 में आवास डेवलपर्स को 15 करोड़ रुपए की मॉर्गेज ओवरड्राफ्ट सुविधा दी गई थी। समय-समय पर इसकी सीमा बढ़ाई गई और 2019 तक यह 135 करोड़ रुपए पहुंच गई। बैंक का दावा था कि 7 अक्टूबर 2019 तक कंपनी पर कुल बकाया 140.12 करोड़ रुपए हो गया था।

■ वहीं आवास डेवलपर्स ने दलील दी कि उसका खाता 31 अगस्त 2012 को ही एनपीए घोषित कर दिया गया था। ऐसे में दिवालियापन कानून के तहत तीन साल की निर्धारित समय सीमा काफी पहले समाप्त हो चुकी थी। कंपनी का कहना था कि दिसंबर 2023 में दाखिल की गई याचिका कानूनी रूप से समय-सीमा से बाहर है। सुनवाई के दौरान एनसीएलटी ने बैंक और कंपनी दोनों की दलीलों तथा रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों की जांच की। ट्रिब्यूनल ने माना कि बैंक ने 7 अक्टूबर 2019 को जारी मांग नोटिस को गलत तरीके से 'डिफॉल्ट की तारीख' माना है। पीठ ने कहा कि मांग नोटिस तब जारी किया जाता है जब उधारकर्ता पहले ही भुगतान करने में विफल हो चुका होता है, इसलिए नोटिस की तारीख को डिफॉल्ट की तारीख नहीं माना जा सकता।

■ हालांकि ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि कंपनी ने अपने ऑडिटेड खातों और 16 अगस्त 2018 के एक पत्र में बकाया राशि स्वीकार की थी। लेकिन इसके बाद कर्ज स्वीकार करने का कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे समय सीमा आगे बढ़ सके। एनसीएलटी ने कहा कि कोविड-19 के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अतिरिक्त राहत को जोड़ने के बाद भी याचिका दाखिल करने की अंतिम तारीख 1 अगस्त 2023 थी। चूंकि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यह याचिका 4 दिसंबर 2023 को दाखिल की, इसलिए यह कानूनी समय सीमा से बाहर मानी जाएगी। ट्रिब्यूनल ने बैंक की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक कानून के तहत उपलब्ध अन्य विकल्पों का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इस मामले में दिवालियापन प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती।

अवैध पानीपुरी कारखाना सील, केडीएमसी की कार्रवाई

गंदगी में बन रही थीं सेव-पुरी और पानीपुरी

हिंदमाता संवाददाता @ कल्याण

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) ने नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले एक अवैध सेव-पुरी और पानीपुरी निर्माण कारखाने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। यह कार्रवाई कल्याण पूर्व के काटेमानिवली क्षेत्र में स्थित कारखाने पर की गई।

अस्वच्छ माहौल में बन रहा था खाद्य पदार्थ

जे वार्ड की सहायक आयुक्त सविता हिले के नेतृत्व में हुई छापेमारी के दौरान कारखाने में भारी गंदगी और बेहद अस्वच्छ वातावरण मिला। जांच में पता चला कि सेव-पुरी और पानीपुरी की पूरियां बेहद खराब एवं निकृष्ट गुणवत्ता के तेल में तली जा रही थीं। खाद्य सामग्री तैयार करते समय स्वच्छता के नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही थी, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था।

कारखाना सील, कार्रवाई जारी

निरीक्षण के बाद महानगरपालिका अधिकारियों ने तत्काल कारखाने को सील कर दिया और बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री तथा अन्य सामान जब्त कर लिया। इस कार्रवाई से अवैध खाद्य निर्माण इकाइयों में हड़कंप मच गया। समाचार लिखे जाने तक कारखाना संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी थी। महानगरपालिका ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा।

भिवंडी में टोरंट पावर का फ्रेंचाइजी मॉडल सबसे सफल

अब मिल रही 24 घंटे बिजली - मुख्यमंत्री

हिंदमाता संवाददाता @ भिवंडी

भिवंडी में टोरंट पावर कंपनी का फ्रेंचाइजी मॉडल राज्य में सबसे सफल साबित हुआ है। बिजली नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने का अधिकार किसी भी फ्रेंचाइजी कंपनी को नहीं है। यह बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कही। विधानसभा में भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि टाटा पावर और अदाणी पावर की तुलना में टोरंट पावर के बिजली दर अधिक हैं, जिससे भिवंडी के उपभोक्ता परेशान हैं। उन्होंने भिवंडी में अन्य निजी बिजली वितरण कंपनियों को भी अवसर देने तथा पावरलूम संचालकों के लिए ब्याज और बकाया बिजली बिलों पर एकमुश्त समझौता योजना लागू करने की मांग की। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भिवंडी में टोरंट पावर का फ्रेंचाइजी मॉडल बेहद सफल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में औसतन 12 से 13 प्रतिशत बिजली हानि होती है, जबकि भिवंडी में इसे घटाकर 10 प्रतिशत तक लाने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टोरंट पावर के आने से पहले भिवंडी शहर को औसतन केवल 16 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन अब यहां 23.56 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। इसके अलावा पहले जहां बिजली बिल वसूली की दर 65 से 67 प्रतिशत थी, वहीं अब यह बढ़कर 98 प्रतिशत तक पहुंच गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली दरों का निर्धारण महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग के नियमों के अनुसार किया जाता है और निर्धारित दरों से अधिक वसूली करने का अधिकार किसी भी फ्रेंचाइजी कंपनी को नहीं है। विधानसभा में इस मुद्दे पर हुई चर्चा के बाद भिवंडी की बिजली व्यवस्था, टोरंट पावर के शुल्क और पावरलूम उद्योग से जुड़े सवाल एक बार फिर राजनीतिक और जनचर्चा के केंद्र में आ गए हैं।

916 रिक्त पदों से जूझ रही मनपा

भिवंडी मनपा में अधिकारियों की भारी कमी

हिंदमाता संवाददाता @ भिवंडी

भिवंडी नगर निगम (मनपा) में अधिकारियों और कर्मचारियों की भारी कमी के कारण प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। निगम में स्वीकृत 4,189 पदों के मुकाबले 916 पद रिक्त हैं। वर्षों से भर्ती और पदोन्नति नहीं होने के कारण वर्ग-3 और वर्ग-4 के कर्मचारियों को प्रभारी अधिकारी बनाकर काम कराया जा रहा है। कई महत्वपूर्ण विभागों का संचालन नियमित अधिकारियों के बजाय प्रभारी कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है, जिससे विकास कार्यों की गति धीमी पड़ गई है।

प्रभारी अधिकारियों के भरोसे काम

स्थापना विभाग के अनुसार आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, दो उपायुक्त, मुख्य वित्त अधिकारी, शहर अभियंता और चिकित्सा अधिकारी जैसे कुछ पदों को छोड़कर अधिकांश प्रमुख पद प्रभारी अधिकारियों के पास हैं। कर मूल्यांकन अधिकारी, विधि अधिकारी, नगर सचिव, स्थापना प्रमुख, शहर विकास अधिकारी तथा पांचों प्रभाग समितियों के प्रभाग अधिकारियों का अतिरिक्त कार्यभार भी प्रभारी कर्मचारियों को सौंपा गया है। कई जगह सफाई कर्मचारी और लिपिक भी प्रभारी अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

भर्ती और पदोन्नति की मांग

मनपा आयुक्त अनमोल सागर ने स्वीकार किया कि कर्मचारियों की भारी कमी है और सरकार से बार-बार मांग के बावजूद पर्याप्त अधिकारी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। नागरिक लोकाधिकार संरक्षण मंच के ठाणे जिला अध्यक्ष कपिल मिश्र ने आरोप लगाया कि प्रभारी व्यवस्था के कारण प्रशासनिक जवाबदेही कमजोर हुई है। वहीं, शहर के नागरिकों ने मांग की है कि सरकार जल्द नियमित अधिकारियों की नियुक्ति और लंबित भर्ती प्रक्रिया पूरी करे, ताकि प्रशासनिक कार्यों में तेजी आए और विकास कार्यों को गति मिल सके।

चार छात्राएं एक ही स्कूल से अचानक लापता

कल्याण में मचा हड़कंप पुलिस के हाथ भी नहीं लगा कोई सुराग

हिंदमाता संवाददाता @ कल्याण

कल्याण इलाके से एक बेहद परेशान और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां के बाजारपेठ पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक प्रतिष्ठित उर्दू हाई स्कूल की चार नाबालिग छात्राएं अचानक एक साथ रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई हैं। एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में पढ़ने वाली चार सहेलियों के इस तरह अचानक गायब होने से पूरे कल्याण शहर में सनसनी फैल गई है। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर हर स्तर पर गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए कल्याण पुलिस आयुक्त कार्यालय और ठाणे जिला पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है, हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा

स्कूल जाने के लिए निकली थीं चारों सहेलियां, देर रात दर्ज हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना 29 जून 2026 की सुबह की है। चारों नाबालिग छात्राएं रोज की तरह अपने-अपने घरों से स्कूल जाने के लिए तैयार होकर निकली थीं। जब दोपहर बाद और फिर शाम ढलने तक लड़कियां अपने घर वापस नहीं लौटीं, तो उनके परिजनों को चिंता होने लगी। परिवारों ने आपस में संपर्क किया और सगे-संबंधियों के यहां भी पूछताछ की, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। देर रात तक जब लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिला, तो घबराए हुए परिजनों ने तुरंत बाजारपेठ पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी बच्चियों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है पुलिस

परिजनों की शिकायत मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत सतर्क हो गया और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस टीमों ने स्कूल परिसर, कल्याण रेलवे स्टेशन, स्थानीय बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड के आसपास लगे दर्जनों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही, तकनीकी शाखा की मदद से लापता लड़कियों के मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया चैट की भी बारीकी से जांच की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के अलग-अलग हिस्सों में पुलिस की विशेष टीमें रवाना की गई हैं।

अपहरण की आशंका से सहमे अभिभावक

एक साथ चार नाबालिग बच्चियों के गायब होने के बाद से स्थानीय नागरिकों और विशेषकर स्कूली बच्चों के माता-पिता के बीच भारी डर और दहशत का माहौल है। पुलिस इस मामले में अपहरण के एंगल से भी गहराई से तफ्तीश कर रही है कि कहीं किसी संगठित गिरोह ने इन बच्चियों को बहला-फुसलाकर अपना शिकार तो नहीं बनाया है। वहीं पुलिस इस संभावना से भी इनकार नहीं कर रही है कि लापता लड़कियां किसी पारिवारिक या व्यक्तिगत तनाव के चलते अपनी मर्जी से कहीं गई हों। फिलहाल, पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने और कोई भी संदिग्ध जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने की अपील की है।

कार हादसे के बाद एक्शन आयुक्त ने किया निरीक्षण

सुरक्षा कार्यों और ड्रेनेज सुधार के दिए निर्देश

हिंदमाता संवाददाता @ वसई

वाघरालपाड़ा में तेज बारिश के दौरान कार बहने की घटना के बाद वसई-विरार शहर महानगरपालिका (वीवीसीएमसी) सक्रिय हो गई है। महानगरपालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. ने गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि लगातार 100 मिमी से अधिक बारिश और पालघर जिले में रेड अलर्ट के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों की सतर्कता से कार चालक की जान बच गई।

सुरक्षा कार्यों को मिलेगी प्राथमिकता

आयुक्त ने बताया कि कलवर्ट पर रेलिंग लगाने, संवेदनशील स्थानों पर पिचिंग करने और अन्य सुरक्षा कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। साथ ही पूरे शहर के लिए व्यापक ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सीडब्ल्यूपीआरएस और एनईईआरआई के तकनीकी सुझावों के आधार पर भविष्य की अत्यधिक वर्षा को ध्यान में रखते हुए जल निकासी व्यवस्था विकसित की जाएगी।

जलमार्ग बहाल करने की मांग

भाजपा नगरसेवक एवं विरोधी पक्ष नेता मनोज पाटिल ने कहा कि प्राकृतिक नालों और जलमार्गों पर अतिक्रमण तथा डायवर्जन के कारण बारिश का पानी बाधित हो रहा है। उन्होंने सभी प्राकृतिक जलमार्गों को मूल स्वरूप में बहाल करने और अतिक्रमण हटाने की मांग की। उनका कहना है कि भविष्य में अधिक बारिश होने पर स्कूलों और नालों के किनारे बसे घरों पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।

नाले के पानी से धोई जा रहीं सब्जियां

विरार के चंदनसार बाजार का वीडियो वायरल

हिंदमाता संवाददाता @ विरार

विरार पूर्व स्थित चंदनसार सब्जी बाजार में नाले के गंदे पानी से सब्जियां धोकर बेचने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नागरिकों में आक्रोश फैल गया है। लोगों ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

खुलेआम धुल रही थीं सब्जियां

चंदनसार सब्जी बाजार में स्थानीय किसान और विक्रेता फल एवं सब्जियां बेचते हैं। यहां बड़ी संख्या में विरार पूर्व के लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। वायरल वीडियो में एक महिला बाजार के सामने बह रहे नाले के गंदे पानी में पत्तेदार सब्जियां धोती हुई दिखाई दे रही है। हैरानी की बात यह है कि यह काम दिनदहाड़े लोगों की मौजूदगी में खुलेआम किया जा रहा था।

स्वास्थ्य पर मंडराया खतरा

नागरिकों का कहना है कि दूषित पानी से धुली सब्जियों के सेवन से संक्रमण और कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लोगों ने इस मामले को स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए वसई-विरार महानगरपालिका और खाद्य एवं औषधि प्रशासन से तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

टीईटी कांड में तीन और गिरफ्तार

पेपर लीक रैकेट के कई अहम राज खुलने की उम्मीद

हिंदमाता संवाददाता @ भिवंडी

महाराष्ट्र के बहुचर्चित टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पेपर लीक मामले में ठाणे पुलिस ने गुरुवार को तीन और आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच को नया मोड़ दे दिया। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान पेपर लीक के पूरे नेटवर्क, आर्थिक लेन-देन और फरार आरोपियों से जुड़े कई अहम खुलासे होंगे।

जम्मू और पटना से गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, लंबे समय से फरार आरोपी कपिल दहिया को लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचना के आधार पर जम्मू से गिरफ्तार किया गया। वहीं, सोनू सिंह और मिथुन सिंह को बिहार के पटना से हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक जांच में दोनों को मुख्य आरोपी बिजेंद्र कुमार गुप्ता का करीबी सहयोगी बताया गया है।

रैकेट की कड़ियां खंगाल रही पुलिस

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पेपर लीक की साजिश किस स्तर पर रची गई, प्रश्नपत्र किस माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाए गए और पूरे नेटवर्क में किन-किन लोगों की भूमिका रही। जांच एजेंसियां मोबाइल कॉल डिटेल, बैंक खातों, डिजिटल साक्ष्यों और आर्थिक लेन-देन की भी गहन पड़ताल कर रही हैं।

कई राज्यों तक फैली जांच

इससे पहले मुख्य आरोपी बिजेंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी की गिरफ्तारी के बाद मिले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस इन आरोपियों तक पहुंची। जांच में सामने आया है कि प्रश्नपत्र आगरा की प्रिंटिंग प्रेस से अवैध रूप से बाहर निकालकर दिल्ली के रास्ते महाराष्ट्र लाए गए थे। फिलहाल तीनों आरोपियों को भिवंडी न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड मांगी जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि जल्द ही इस रैकेट से जुड़े कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं।

भिवंडी में खुला आउटलेट मॉल

हिंदमाता संवाददाता @ भिवंडी

मुंबई-नासिक हाईवे पर पिंपलास गांव स्थित भूमी वर्ल्ड परिसर में गुरुवार को 'आउटलेट मॉल ऑफ इंडिया' का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद मॉल आम ग्राहकों के लिए खोल दिया गया। मॉल प्रबंधन का दावा है कि यहां देशी-विदेशी नामी ब्रांडों के उत्पाद पूरे वर्ष 70 प्रतिशत तक की छूट पर उपलब्ध होंगे। मॉल के मुख्य प्रवर्तक प्रकाश पटेल ने बताया कि यहां फैशन, फुटवियर, स्पोर्ट्सवियर, घड़ियां, ज्वेलरी, बैग, एक्सेसरीज और अन्य लाइफस्टाइल उत्पाद रियायती कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। उद्योगपति नानजी पटेल भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। प्रबंधन के अनुसार, मॉल में खरीदारी के साथ फूड आउटलेट और आधुनिक मनोरंजन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे यह एक संपूर्ण रिटेल एवं लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन बनेगा। प्रकाश पटेल ने कहा कि मुंबई-नासिक हाईवे और समृद्धि महामार्ग से बेहतर कनेक्टिविटी के कारण यहां बड़ी संख्या में ग्राहकों के आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मॉल में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

टीवीके के विधायक तोड़ने के लिए 35-35 करोड़ का खेल

•संजय राऊत का बीजेपी पर बड़ा आरोप

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

महाराष्ट्र में जारी भीषण राजनीतिक उठापटक और शिवसेना (यूबीटी) में लगातार हो रही टूट के बीच, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राऊत ने केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर अब तक का सबसे तीखा और जुबानी हमला बोला है। संजय राऊत ने विपक्षी दलों को तोड़े जाने की राजनीति पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ताधारियों को पार्टियां विभाजित करने का ऐसा नशा चढ़ चुका है कि आने वाले समय में वे खुद को ही तोड़ना शुरू कर देंगे। संजय राऊत ने इसके साथ ही उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति को लेकर एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला दावा भी किया है। उन्होंने कहा, टीवीके के विधायकों को तोड़ने के लिए 35-35

करोड़ रुपए का बड़ा खेल शुरू हो चुका है।

देश का लोकतंत्र खत्म हो गया है

संजय राऊत ने देश और राज्य में चल रही दल-बदल की राजनीति पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा, 'मुझे तो ऐसा लगता है कि एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक साथ बैठेंगे और बोलेंगे कि मैं तुझे फोड़ता हूं और तू मुझे फोड़, क्योंकि देश में अब पार्टी तोड़ने के लिए कोई दूसरा दल बचेगा ही नहीं। इन लोगों को विपक्ष को तोड़े बिना चैन नहीं पड़ता और रात में नींद नहीं आती है। देश का लोकतंत्र इतने निचले स्तर पर गिर चुका है कि हमें आने वाली पीढ़ियों को यह बताना पड़ेगा कि कभी इस देश में लोकतंत्र हुआ करता था।'

टीवीके सरकार गिराने के लिए 35-35 करोड़ के खेल का आरोप

महाराष्ट्र से बाहर की राजनीति का जिक्र करते हुए संजय राऊत ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में भी विपक्षी दलों को अस्थिर करने की बड़ी साजिश रची जा रही है। राऊत ने कहा, 'तमिलनाडु में टीवीके के विधायकों को तोड़ने के लिए 35-35 करोड़ रुपए का बड़ा खेल शुरू हो चुका है। वहां करीब 15 विधायकों को लालच देकर तोड़ने और टीवीके सरकार को गिराने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों और अथाह पैसे के बल पर पूरे देश में विपक्ष की चुनी हुई सरकारों और पार्टियों को नष्ट किया जा रहा है।

10 मिनट में हो जाएंगे बीजेपी के 10 टुकड़े

संजय राऊत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए महायुति और बीजेपी को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि आज यह लोग सत्ता की हनक में विपक्ष को प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये लोग सत्ता से बाहर होंगे और सुरक्षा एजेंसियां हमारे नियंत्रण में आएंगी, तो बीजेपी के 10 मिनट के भीतर 10 टुकड़े हो जाएंगे। न एकनाथ शिंदे का गुट बचेगा, न अजित पवार का खेमा और न ही खुद बीजेपी टिक पाएगी। सिर्फ एक घंटे के लिए ईडी और सीबीआई हमारे हवाले कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है।' इसके साथ ही, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर चल रहे ताजा विवाद पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। राऊत ने मांग की कि इस मामले में केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जांच एजेंसियों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है, तो इस घोटाले में शामिल गंभीर आरोपियों जैसे चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

मुझे पहले अपनी पारी खेलने दीजिए

महाराष्ट्र विधानपरिषद के नये उपसभापति सचिन अहीर

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के प्रत्याशी के तौर पर विधानपरिषद के उपसभापति पद के लिए निर्वाचित हुए सचिन अहीर ने गुरुवार को अपनी भविष्य की राजनीतिक भूमिका को लेकर लगाई जा रही अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि मुझे पहले अपनी पारी खेलने दीजिए। वैसे अहीर विपक्षी शिवसेना (उबाठा) के विधानपरिषद सदस्य हैं।

अच्छा स्कोर बनाने दीजिए

अहीर ने आज विधानभवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि मुझे लगता है कि मैं अकेला ही काफी हूं, इसलिए पहले मुझे अपनी पारी खेलने दीजिए। पहले मुझे अच्छा स्कोर बना लेने दीजिए, उसके बाद हम और खिलाड़ियों को शामिल करने के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना कार्यकर्ताओं समेत वर्ली के लोग मेरे साथ हैं। आखिरकार, वे मेरे ही कार्यकर्ता हैं।

नामांकन से बढ़ी चर्चा

शिवसेना (उबाठा) नेता आदित्य ठाकरे के भरोसेमंद सहयोगी माने जाने वाले अहीर ने मंगलवार को उस समय सबको चौंका दिया, जब उन्होंने सत्ताधारी शिवसेना के उम्मीदवार के तौर पर उपसभापति पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया।

राजनीतिक सफर

मुंबई के वर्ली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अहीर ने तत्कालीन अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर यह सीट जीती थी और बाद में राज्य मंत्री के तौर पर अपनी सेवा दी। उन्हें 2029 के विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायक आदित्य ठाकरे के खिलाफ भावी शिवसेना प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है।

शिंदे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया

वह शिवसेना के प्रमुख एवं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि क्रिकेट के जादूगर सचिन तेंदुलकर की तरह अहीर 'बड़ी पारी' खेलेंगे। अहीर ने मंगलवार को विधानपरिषद के उपसभापति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। उसके बाद शिंदे ने यह टिप्पणी की थी।

आदित्य का दावा

आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि अहीर ने (उपसभापति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद) उन्हें बताया था कि वह 2029 का विधानसभा चुनाव वर्ली से नहीं लड़ेंगे। हालांकि शिवसेना (उबाठा) नेता आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसे आश्वासन पर भरोसा नहीं है।

शिवसेना (उबाठा) को झटका

शिवसेना (उबाठा) से अहीर का निकल जाना, मध्य मुंबई के वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन से नेता बने अरुण गवली के भतीजे अहीर, अविभाजित राकांपा के तीन बार विधायक रहे और 1999-2014 के दौरान कांग्रेस-राकांपा गठबंधन की सरकार में मंत्री भी रहे। वह अविभाजित राकांपा की मुंबई इकाई के प्रमुख भी रहे हैं। अहीर 2014 में अविभाजित शिवसेना के प्रत्याशी सुनील शिंदे के हाथों विधानसभा चुनाव हार गये थे।

2019 से आदित्य के करीबी

आदित्य ठाकरे के 2019 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ने और विजयी होने से पहले अहीर अविभाजित शिवसेना में शामिल हुए थे। तब से अहीर आदित्य के करीब थे और उन्हें श्रमिक संगठन समेत पार्टी से जुड़े कई संगठनों की जिम्मेदारी दी गयी। अहीर 2022 में विधानपरिषद के सदस्य चुने गए थे और सदन में उनका कार्यकाल 2028 तक है।

पार्टियां तोड़ते-तोड़ते एक दिन मोदी और शाह खुद एक-दूसरे को ही तोड़ देंगे!

संजय राऊत का भाजपा पर तीखा हमला

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

शिवसेना (यूबीटी) के फायरब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद संजय राऊत ने भाजपा आलाकमान पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए राऊत ने दावा किया कि भाजपा नेताओं में विपक्षी दलों को तोड़ने का एक अलग ही नशा सवार है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आने वाले दिनों में जब देश में कोई दूसरी पार्टी तोड़ने के लिए नहीं बचेगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक-दूसरे को ही तोड़ने पर आमादा हो जाएंगे।

संजय राऊत का मोदी शाह पर बड़ा हमला

उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राऊत ने कहा कि मौजूदा समय में भाजपा के नेता जिस तरह से काम कर रहे हैं, उससे एक बात साफ हो चुकी है कि आने वाले दिनों में स्थिति ऐसी हो जाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक दूसरे को ही तोड़ने पर आमादा हो जाएंगे। संजय राऊत ने कहा कि भाजपा के लोगों में एक-दूसरे को तोड़ने का बहुत ही ज्यादा नशा है। आने वाले दिनों में जब इन लोगों के पास कोई भी पार्टी तोड़ने के लिए नहीं रहेगी, तो ये लोग एक-दूसरे को ही तोड़ने पर आमादा हो जाएंगे। यह स्थिति राजनीति के लिहाज किसी भी स्थिति में मान्य नहीं मानी जा सकती है।

तमिलनाडु में 35-35 करोड़ के खेल का आरोप

तमिलनाडु के राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए संजय राऊत ने कहा कि मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि तमिलनाडु में एक या दो नहीं बल्कि 35-35 करोड़ रुपए का खेल हुआ है। टीवीके के 15 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई है। इन विधायकों को तोड़ने का सीधा मकसद सरकार गिराने से था। इन लोगों को चैन नहीं है और इन्हें नींद नहीं आती है। जब तक ये लोग किसी पार्टी को तोड़ नहीं लेते हैं, तब तक इन्हें नींद नहीं आती है। साथ ही, शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राऊत ने कहा कि मौजूदा समय में स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आगामी दिनों में हमें यह बताना होगा कि कभी इस देश में लोकतंत्र हुआ करता था। इन लोगों ने पूरी तरह से लोकतंत्र को समाप्त करके रख दिया है। इन लोगों ने लोकतंत्र के सिद्धांतों पर कुठाराघात किया है।

सिर्फ 1 घंटे के लिए ईडी-सीबीआई दे दो, 10 मिनट में करेंगे 10 टुकड़े : राऊत

संजय राऊत ने कहा कि मौजूदा समय में जिस तरह की स्थिति चल रही है, उसे देखते हुए भविष्य में विपक्षी दलों की स्थिति अप्रासंगिक हो जाएगी, क्योंकि ये लोग केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लेकर हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात दावे के साथ कह देना चाहता हूं कि जिस दिन बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी और हम सत्ता में आए, तो केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लेकर इनकी पार्टी के 10 टुकड़े कर देंगे, वो भी महज 10 मिनट में। सिर्फ एक घंटे के लिए ईडी और सीबीआई को हमारे हवाले कर दिया जाए तो यह होने में देर नहीं लगेगी।

पुणे में दारोगा को दबंगई करना पड़ा महंगा

कैफे में बदसलूकी का वीडियो हुआ था वायरल, हुआ निलंबित

हिंदमाता नेटवर्क @ पुणे

पुणे में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर (दारोगा) को कैफे में बदसलूकी करना महंगा पड़ गया। दरअसल इसका वीडियो वायरल होने के बाद दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। घटना 6 जून की रात की है, जिस पर अब एक्शन हुआ है।

क्या है पूरा मामला?

पुणे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डेक्कन पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर संदीप कदम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सब-इंस्पेक्टर पर एक स्थानीय कैफे के कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद विभाग ने यह सख्त कदम उठाया।

नाइट ड्यूटी के दौरान दारोगा ने की थी बदसलूकी

यह घटना 6 जून की रात की है, जब सब-इंस्पेक्टर संदीप कदम नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। रात के करीब 1:45 बजे, वह शिरोल रोड स्थित 'फ्लाइंग जिप्सी' कैफे में दाखिल हुए। उस समय कैफे बंद होने की तैयारी में था। कैफे में लगे सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, सब-इंस्पेक्टर कदम ने कैफे के भीतर जाकर जमकर हंगामा किया।

छठी की किताब में महाराष्ट्र के लोक नृत्यों की अनदेखी

बालभारती के नए सिलेबस पर क्यों भड़के विद्वान?

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

महाराष्ट्र में इस साल से स्कूली शिक्षा में सीबीएसई प्रणाली को लागू किया गया है, जिसके तहत मराठी को एक अनिवार्य विषय बनाया गया है। सरकार के इस फैसले की सराहना तो हुई, लेकिन अब शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। बालभारती द्वारा कक्षा 6 के लिए तैयार की गई मराठी की पाठ्यपुस्तक में शामिल लोक नृत्य के एक पाठ को लेकर राज्य के शिक्षाविदों और सांस्कृतिक विशेषज्ञों में भारी आक्रोश है।

क्या है पूरा विवाद?

विवाद की मुख्य वजह इस पाठ में महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की अनदेखी करना है। पुस्तक के इस अध्याय में कुल पांच लोक नृत्यों का वर्णन किया गया है। हैरानी की बात यह है कि इन पांच नृत्यों में से केवल एक लोक नृत्य महाराष्ट्र का है, जबकि शेष चार नृत्य अन्य राज्यों के शामिल किए गए हैं।

इन राज्यों के लोक नृत्यों को किया गया शामिल

किताब में महाराष्ट्र के सिर्फ 'वारकरी दिंडी' नृत्य को जगह मिली है। वहीं, अन्य राज्यों के नृत्यों की बात करें तो इसमें गुजरात का रास नृत्य, पंजाब का भांगड़ा, बिहार का आदिवासी नृत्य और छत्तीसगढ़ का बस्तर नृत्य शामिल किया गया है।

विशेषज्ञों और लेखकों ने जताई कड़ी आपत्ति

मशहूर लेखक श्रीपाद भालचंद्र जोशी सहित शिक्षा क्षेत्र के कई विद्वानों और सांस्कृतिक विशेषज्ञों ने महाराष्ट्र की समृद्ध लोक परंपराओं शामिल नहीं किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब छात्र प्राथमिक स्तर में पढ़ रहे हों, तो उन्हें सबसे पहले अपने राज्य की समृद्ध संस्कृति और इतिहास से परिचित कराया जाना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र के पास लावणी, लेजिम, धनगरी गजा, गोंडल, कोली नृत्य और पोवाड़ा जैसी अत्यंत समृद्ध और ऊर्जावान लोक नृत्य परंपराएं हैं। विशेषज्ञों का तर्क है कि इन सभी विधाओं को पाठ के अलग-अलग अनुभागों में आसानी से शामिल किया जा सकता था, लेकिन बालभारती ने इसकी अनदेखी की है। इसलिए, अब इस पाठ का विरोध हो रहा है और देखना यह होगा कि सरकार इस पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं।

देश में लोकतंत्र खतरे में, नागरिक आवाज उठाएं : कांग्रेस नेता नटराजन

'वोट चोरी, सीट चोरी और पार्टी चोरी' के बाद, केंद्र सरकार अब ''नागरिकता छीनने'' की कोशिश

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन ने गुरुवार को देश में लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा होने का आरोप लगाया और कहा कि 'वोट चोरी, सीट चोरी और पार्टी चोरी' के बाद, केंद्र सरकार अब ''नागरिकता छीनने'' और लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर रही है।

सम्मेलन को संबोधन

मुंबई स्थित तिलक भवन में महाराष्ट्र कांग्रेस की 'लोकशाही वाचवा निर्धार सभा' (लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन) को संबोधित करते हुए नटराजन ने कहा कि नागरिकों को लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए।

नामांकन खारिज होने का जिक्र

राज्यसभा चुनाव का अपना नामांकन पत्र खारिज होने का जिक्र करते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, न कि सिर्फ उनके साथ व्यक्तिगत अन्याय।

भाजपा पर निशाना

नटराजन ने कहा कि जरूरी संख्या बल न होने के बावजूद, मध्य प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा ने तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारा। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव अधिकारियों ने उन्हें आपत्तियों का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय या मौका नहीं दिया।

जनता के गुस्से का उल्लेख

नटराजन ने कहा कि इस घटना पर जनता का गुस्सा लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर बढ़ती चिंता को दिखाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जन सभा, राज्यसभा से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

सपकाल का बयान

कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने नटराजन का नामांकन पत्र खारिज किए जाने को ''लोकतंत्र पर हमला'' बताया।

'दूसरे स्वतंत्रता संग्राम' की बात

सपकाल ने कहा कि देश ''करो या मरो'' जैसी स्थिति से गुजर रहा है, जिसके लिए संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए ''दूसरे स्वतंत्रता संग्राम'' की जरूरत है।

लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव

विधानपरिषद में कांग्रेस के नेता सतेज पाटिल ने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्ष में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ा है। उन्होंने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया।

पुलिस हिरासत में पीट-पीटकर मौत मामले में 9 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद

15 साल बाद आया फैसला

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

वाशिम जिला एवं सत्र न्यायालय ने पुलिस हिरासत में हुई मौत के बहुचर्चित मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। रिसोड पुलिस स्टेशन में चोरी के मामले में संदिग्ध बेग्या पवार की कथित पुलिस पिटाई से हुई मौत के मामले में अदालत ने तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 9 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला घटना के करीब 15 साल बाद आया है।

हिरासत में पिटाई से चली गई थी जान

यह मामला 10 मई 2011 का है, जब रिसोड पुलिस स्टेशन में चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए लाए गए संदिग्ध बेग्या पवार की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। आरोप था कि पुलिसकर्मियों की पिटाई के कारण उसकी जान गई।

सीआईडी ने की थी इस मामले की जांच

इस मामले की जांच सीआईडी ने की थी। 34 दिनों की जांच के बाद सीआईडी ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या और विशेष अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

सामने आए पुलिसकर्मियों के नाम

लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद वाशिम के जिला एवं सत्र न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पूरी हुई। वाशिम के जिला एवं सत्र न्यायालय के जिला न्यायाधीश जयसिंग झपाटे ने सुनवाई पूरी होने के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी महादेव माणिक धांडे सहित मदन केशव पवार, शिवाजी नामदेव खिल्लारी, पंजाब माणिकराव पाटकर, रमेश सीताराम पवार, प्रकाश हिरालाल तारम, नागोराव भगवान खांडके, अशोक निवृत्ती वैद्य और वसंत कणिराम जाधव हैं। कुल 9 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

परिजनों ने कहा : आखिर मिल गया न्याय

अदालत के इस फैसले के बाद मृतक बेग्या पवार के परिजनों ने राहत और संतोष व्यक्त किया। परिवार का कहना है कि न्याय मिलने के लिए उन्हें लगभग डेढ़ दशक तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन आखिरकार अदालत ने दोषियों को सजा देकर न्याय किया। परिजनों ने उम्मीद जताई कि इस फैसले से भविष्य में पुलिस हिरासत में होने वाली ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और कानून का दुरुपयोग करने वालों को कड़ा संदेश जाएगा। साथ ही मृतक के पिता नयणु फैसल्या पवार ने कहा कि उनके परिवार ने वर्षों तक न्याय के लिए संघर्ष किया।

आयुक्त तुकाराम मुंढे के आदेश

एफडीए ने दो रेस्तरां के लाइसेंस को किया निलंबित

हिंदमाता नेटवर्क @ छत्रपति संभाजीनगर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शहर के दो प्रमुख रेस्तरां के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके खाद्य व्यवसाय लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिए हैं। जांच के दौरान कृत्रिम रंगों का उपयोग, फफूंद लगी सब्जियां और खाद्य सामग्री, रसोई में गंदगी तथा ग्राहकों के लिए निःशुल्क पेयजल उपलब्ध होने संबंधी सूचना पट्ट नहीं मिलने जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। सह आयुक्त (खाद्य) श्रीरा. करकले ने बताया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंडे के 23 जून के निर्देशों के अनुसार छत्रपति संभाजीनगर संभाग के होटलों और रेस्तरां में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पिछले दो दिनों से शहर के यल्ला-यल्ला रेस्तरां (गजानन महाराज मंदिर रोड) तथा आईच्या गावात रेस्तरां (इतखेड़ा) का निरीक्षण किया गया।

लाइसेंस निलंबित करने का कारण

जांच में यल्ला-यल्ला रेस्तरां में बटर चिकन, पनीर ग्रीन, हरियाली कबाब, चिकन लॉलीपॉप सहित कई व्यंजनों तथा तैयार ग्रेवी में कृत्रिम खाद्य रंगों का उपयोग पाया गया। अधिकारियों ने मौके से रंग के डिब्बे जब्त कर नष्ट कर दिए। रसोई में गंदगी, फफूंद लगी सब्जियां, खुले में रखी ग्रेवी तथा अस्वच्छ तरीके से रखी कच्ची खाद्य सामग्री भी मिली। इसके अलावा ग्राहकों को निःशुल्क पेयजल उपलब्ध होने का अनिवार्य सूचना पट्ट भी नहीं लगा था। वहीं, आईच्या गावात रेस्तरां में बटर के स्थान पर प्रोफेशनल फैट स्प्रेड का उपयोग कर ग्राहकों को बटर तंदूरी रोटी, बटर नान और अन्य व्यंजन परोसे जा रहे थे। निरीक्षण में फफूंद लगी खाद्य सामग्री और पत्तेदार सब्जियां, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए प्लास्टिक के ड्रम का उपयोग, कच्ची खाद्य सामग्री और कूड़ेदान को एक ही स्थान पर रखा जाना तथा कृत्रिम रंगों का उपयोग भी पाया गया। यहां भी निःशुल्क पेयजल संबंधी सूचना पट्ट नहीं लगाया गया था।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन किसे चेतावनी दी!

गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए दोनों रेस्तरां के खाद्य व्यवसाय लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त द. वि. पाटील तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी व. ता. रोडे और की. ल. झाड़े की टीम ने संयुक्त रूप से की। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों को निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी है।

हिंदमाता एंकरः घाटकोपर-अंधेरी के बीच शुरू होगी मिक्स्ड लूप सेवा, भीड़ होगी कम

मुंबई मेट्रो-1 यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

मुंबई मेट्रो-1 से सफर करने वाले लाखों यात्रियों को जल्द राहत मिलने वाली है। घाटकोपर-अंधेरी सेक्शन पर मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए 'मिक्स्ड लूप' सेवा शुरू की जाएगी। इस नई व्यवस्था से पीक आवर्स में प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में होने वाली भीड़ कम होगी। इसी के साथ ही हर घंटे करीब 20,000 अतिरिक्त यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि 11.4 किमी लंबे मेट्रो-1 कॉरिडोर में वसोर्वा से घाटकोपर के बीच 12 स्टेशन हैं। फिलहाल इस मार्ग पर चार-कोच वाली मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं।

5 लाख यात्री करते हैं सफर

वित्तीय सीमाओं के कारण मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड अतिरिक्त ट्रेनें खरीदने और छह-कोच सेवाएं शुरू करने की स्थिति में नहीं है। कार्यदिवसों में इस कॉरिडोर पर 5 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं, जिससे कार्यालय समय में भारी भीड़ रहती है। पूर्व उपनगर के साथ ही ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और बदलापुर से आने वाले अधिकांश यात्री घाटकोपर से मेट्रो पकड़ते हैं। यही कारण है कि करीब 88 प्रतिशत यात्री घाटकोपर-अंधेरी सेक्शन का उपयोग करते हैं।

नई व्यवस्था के तहत चलेंगी कुछ ट्रेनें

पिछले वर्ष शुरू की गई शॉर्ट लूप सेवा से पीक आवर्स में करीब 10,000 अतिरिक्त यात्रियों को सुविधा मिली थी। इस बार क्षमता बढ़ाकर 20,000 अतिरिक्त यात्रियों प्रति घंटा करने का लक्ष्य रखा गया है। नई व्यवस्था के तहत कुछ ट्रेनें केवल घाटकोपर से अंधेरी तक चलेंगी और वहीं से वापस लौटेंगी, जबकि अन्य मुंबई ट्रेनें वसोर्वा तक नियमित रूप से संचालित होंगी। इससे सबसे व्यस्त सेक्शन पर अधिक ट्रेनें उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही मेट्रो सेवाओं की फ्रीक्वेंसी में 6 से 7 प्रतिशत वृद्धि होगी और प्रतिदिन ट्रिप्स की संख्या बढ़कर 482 तक पहुंच सकेगी।

उपलब्ध होगी आरामदायक यात्रा

पीक आवर्स में घाटकोपर-अंधेरी के बीच मुंबई मेट्रो की ट्रेनें हर 3 मिनट 8 सेकंड के अंतराल पर चलेंगी। मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्यामंतक चौधरी ने कहा कि मिक्स्ड लूप व्यवस्था उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर यात्रियों को अधिक तेज, सुगम और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराएगी।

महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके जाने पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी

कहा- बीजेपी सरकार की ओर से भीड़...

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अंडे फेंकने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर विवाद शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी की पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने महुआ के साथ खड़े होने की बात कही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार की ओर से भीड़ को जिस तरह का बढ़ावा मिल रहा है, वह शर्मनाक है। एक महिला सांसद पर अंडे फेंके जाते हैं और पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है। यह बेहद अपमानजनक है। कानून-व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है और सीएम सुवेंदु अधिकारी को अपनी बात पर अमल करना चाहिए। उन्होंने आखिर में लिखा हम महुआ मोइत्रा के साथ खड़े हैं।

बैठक के दौरान फेंके गए अंडे

महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि वह अपने लोकसभा क्षेत्र में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रही थीं। इसी दौरान बीजेपी समर्थक वहां पहुंच गए और बाहर से अंडे फेंकने लगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो जारी कर कहा, "पश्चिम बंगाल के डीजीपी मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं।" उन्होंने आगे लिखा, "मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के कार्यालय में बैठक कर रही थी। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग पार्टी कार्यालय के बाहर एकत्र हो गए। ये लोग खिड़की के जरिए अंडे और पत्थर फेंक रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा फेंके गए अंडे और पत्थर उन्हें भी लगे हैं और उनके कपड़े भी खराब हो गए। उन्होंने कहा, "मैंने पुलिस को फोन किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। मैंने आपको फोन किया, उसके बाद पुलिस आई, लेकिन वह भी सिर्फ तमाशा देख रही है।

विचार प्रवाह

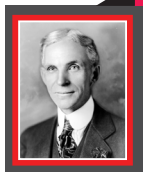

जो कोई भी सीखना छोड़ देता है वो बूढ़ा है, चाहे वो बीस का हो या अस्सी का। जो कोई भी सीखता रहता है वो जवान है। दुनिया की सबसे महान चीज है अपने दीमाग को युवा बनाये रखना।

- हेनरी फोर्ड

संपादकीय

बेलगाम होता भ्रष्टाचार

देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के दावे लगातार किए जाते हैं, लेकिन समय-समय पर सामने आने वाले बड़े घोटाले इन दावों की पोल खोल देते हैं। हाल ही में तीन करोड़ रुपए की कथित रिश्वत लेने के आरोप में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है। यह मामला केवल एक अधिकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि उस सोच और व्यवस्था की ओर इशारा करता है, जिसमें प्रभाव और पद का दुरुपयोग कर कानून को भी प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। आरोप है कि संबंधित अधिकारी ने नकली दवा बनाने वाले एक कारोबारी को जांच से बचाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का भरोसा दिया और इसके बदले भारी रिश्वत ली। यदि जांच में ये आरोप सही साबित होते हैं, तो यह न केवल कानून के रखवालों की साख पर सवाल है, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की विश्वसनीयता पर भी गहरा आघात है। ऐसे मामलों से जनता का न्याय व्यवस्था और सरकारी संस्थानों पर भरोसा कमजोर होता है। दुर्भाग्य यह है कि ऐसे मामले अब अपवाद नहीं रह गए हैं। आए दिन किसी न किसी विभाग के अधिकारी के यहां छापे पड़ते हैं, करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति बरामद होती है और गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन इसके बावजूद बहुत कम मामलों में दोषियों को समय पर और कठोर सजा मिल पाती है। लंबी न्यायिक प्रक्रिया और विभागीय कार्रवाई में देरी का लाभ भ्रष्ट अधिकारी उठाते हैं। यही कारण है कि भ्रष्टाचार का जोखिम कम और लाभ अधिक दिखाई देता है, जिससे इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इसी बीच दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में सामने आया लगभग 650 करोड़ रुपए का कथित घोटाला भी प्रशासनिक भ्रष्टाचार की भयावह तस्वीर पेश करता है। आरोप है कि जरूरत से कहीं अधिक मात्रा में और कई गुना ऊंची कीमतों पर दवाएं एवं उपकरण खरीदे गए। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी धन का उपयोग जनहित के बजाय निजी लाभ के लिए किया गया। जांच एजेंसियों की कार्रवाई में कई अधिकारियों की भूमिका भी सामने आई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भ्रष्टाचार संगठित रूप ले चुका है। स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह की अनियमितताएं केवल आर्थिक अपराध नहीं हैं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन से भी जुड़ी हैं। जब सरकारी धन का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, तो अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण दवाएं और आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते। इसका सबसे अधिक नुकसान गरीब और जरूरतमंद मरीजों को उठाना पड़ता है, जो पूरी तरह सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। नौकरशाही में बढ़ता भ्रष्टाचार अब एक गंभीर राष्ट्रीय चुनौती बन चुका है। यह केवल सरकारी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि विकास योजनाओं की गति धीमी करता है, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता घटाता है और ईमानदार अधिकारियों का मनोबल भी कमजोर करता है। जब भ्रष्टाचार करने वालों को समय पर दंड नहीं मिलता, तो व्यवस्था में गलत संदेश जाता है कि प्रभाव और पहुंच के बल पर कानून से बचा जा सकता है। भ्रष्टाचार पर वास्तविक नियंत्रण केवल छापेमारी और गिरफ्तारियों से संभव नहीं होगा। इसके लिए त्वरित न्याय, पारदर्शी जांच, समयबद्ध विभागीय कार्रवाई और दोष सिद्ध होने पर कठोर दंड सुनिश्चित करना होगा। साथ ही सरकारी खरीद प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना होगा। जब तक भ्रष्टाचार की कीमत लाभ से अधिक नहीं होगी, तब तक इस पर प्रभावी अंकुश लगाना कठिन रहेगा। सुशासन की पहली शर्त यही है कि कानून सब पर समान रूप से लागू हो और सार्वजनिक पद को निजी लाभ का माध्यम बनाने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा न जाए।

आज का इतिहास

- 1972 - भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुए।
- 1989 - सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति आन्द्रेई ग्रोमिको का निधन।
- 1992 - रियो डि जेनरो (ब्राजील) में पृथ्वी सम्मेलन की शुरूआत।
- 1999 - कुवैत में 50 सदस्यीय संसदीय चुनाव सम्पन्न।
- 2000 - लायसेनिया करासे फिजी के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त।
- 2004 - रूस की मारिया शारापोवा महिला विम्बलडन चैम्पियन बनीं।
- 2005 - महेश भूपति और मेरी पियर्स ने विंबलडन टेनिस का मिश्रित युगल खिताब जीता।
- 2006 - कैरेबियाई द्वीप पर 35 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार जीत दर्ज की। स्पेन ने भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद जताई।
- 2007 - विवादास्पद लेखक सलमान रूश्दी ने अपनी पत्नी पद्म लक्ष्मी से तलाक लेने की घोणा की।
- 2008 - न्यूयार्क में दलितों का सम्मेलन शुरू हुआ।
- 2017- अचल कुमार ज्योति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए।
- 1969 - दिगेन्द्र सिंह - 'महावीर चक्र' से सम्मानित वीर भारतीय सैनिक हैं।
- 1979 - आरती सिंह राव - भारतीय निशानेबाज हैं।
- 1616 - शाह शुजा (मुगल) - मुगल बादशाह शाह जहां का पुत्र
- 1952 - रोहिंटन मिस्त्री - प्रख्यात भारतीय कैनेडियन उपन्यासकार हैं।
- 1941 - अदूर गोपालकृष्णन - मलयालम सिनेमा और भारत के चोटी के फिल्म निमार्ताओं में से एक।
- 1897 - हंसा मेहता - भारत की प्रसिद्ध समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद।
- 1892 - हबीब उर रहमान लुधियानवी - भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे।
- 1886 - रामचंद्र दत्तात्रेय रानाडे - दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के अध्यक्ष थे।
- 2020 - सरोज खान - प्रसिद्ध भारतीय कोरियोग्राफर थीं।
- 2019 - सुदर्शन अग्रवाल - उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम के भूतपूर्व राज्यपाल थे।
- 2015 - योगेश कुमार सभरवाल - भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 36वें भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश।
- 1948 - मोहम्मद उस्मान - भारतीय सेना के उच्च अधिकारी, जो भारत और पाकिस्तान के प्रथम युद्ध (1947-48) में शहीद हुए थे।
- 1982 - केदार पांडे - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ तथा बिहार के मुख्यमंत्री थे।
- 1996 - राज कुमार - हिन्दी फिल्म अभिनेता।
- 1999 - मनोज कुमार पांडेय, परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक

चीन प्लस-वन रणनीति का नया केंद्र बनता उत्तर प्रदेश

यूपी वैश्विक विनिर्माण एवं लॉजिस्टिक्स हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा

हिंदमाता नेटवर्क @ उत्तर प्रदेश

किसी भी राष्ट्र के आर्थिक इतिहास में कुछ ऐसे अवसर आते हैं, जो केवल एक परियोजना नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाले मील के पत्थर बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन और व्यावसायिक उड़ानों की शुरूआत भी ऐसा ही ऐतिहासिक क्षण है। यह केवल एक नया हवाई अड्डा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक संभावनाओं, औद्योगिक विकास और वैश्विक संपर्क का नया अध्याय है।

भू-अर्थशास्त्र की दृष्टि से यह परियोजना राज्य को नई पहचान देने वाली है, क्योंकि यह भूगोल, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक महत्व का संगम बनकर उभर रही है। लंबे समय तक समुद्री मार्गों से दूर होने के कारण उत्तर प्रदेश जिस सीमा में बंधा रहा, अब वह बाधा धीरे-धीरे समाप्त होती दिखाई दे रही है।

भूबद्ध राज्य को वैश्विक बाजारों से जोड़ने की पहल

लगभग 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश दुनिया की सबसे बड़ी उप-राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इसके बावजूद समुद्री व्यापार मार्गों तक सीधी पहुंच न होने के कारण राज्य की औद्योगिक और निर्यात क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर हवाई अड्डे के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि यह परियोजना राज्य के एमएसएमई, कृषि, हस्तशिल्प और बड़े उद्योगों को सीधे वैश्विक बाजारों से जोड़ेगी। उनका मानना है कि यह हवाई अड्डा केवल यात्रियों की सुविधा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश के आर्थिक विकास का प्रमुख प्रवेश द्वार बनेगा और निवेश तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।

एरोट्रोपोलिस मॉडल से बदलेगी औद्योगिक तस्वीर

■ जेवर हवाई अड्डे की वर्तमान क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों और 2.5 लाख टन कार्गो की है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर सात करोड़ यात्रियों और 10 लाख टन कार्गो तक ले जाने की योजना है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता 'एरोट्रोपोलिस' की अवधारणा है, जिसमें हवाई अड्डे के आसपास उद्योग, व्यापार, लॉजिस्टिक्स और सेवाओं का विशाल नेटवर्क विकसित किया जाता है। एयर इंडिया सैट्स द्वारा संचालित मल्टी-मॉडल कार्गो हब, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा एचसीएल-फॉक्सकॉन के सेमीकंडक्टर संयंत्र जैसी परियोजनाएं इसी सोच का हिस्सा हैं। इसके अलावा अनेक बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में हजारों करोड़ के निवेश की घोषणा कर चुकी हैं, जिससे यह इलाका उत्तर भारत का नया औद्योगिक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।

चीन प्लस-वन रणनीति का मजबूत विकल्प

■ कोविड महामारी के बाद दुनिया की बड़ी कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखला को केवल चीन तक सीमित रखने के बजाय अन्य देशों में भी विस्तार देने की नीति अपना रही हैं, जिसे 'चीन प्लस-वन' रणनीति कहा जाता है। भारत इस रणनीति का बड़ा लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है और उत्तर प्रदेश इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नोएडा और जेवर क्षेत्र में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्माण से जुड़े उद्योगों का तेजी से विस्तार हो रहा है। यहां पहले से सैमसंग, हैवेल्स, अंबर एंटरप्राइजेज, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य प्रमुख कंपनियों की मौजूदगी है। एचसीएल-फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर संयंत्र इस क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाएगा। यहां बनने वाली चिप्स मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग होंगी, जिनकी वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है।

लॉजिस्टिक्स और विमानन क्षेत्र को मिलेगा नया आयाम

■ जेवर केवल औद्योगिक उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत के उत्तरी क्षेत्र के लिए वैश्विक लॉजिस्टिक्स हब बनने की क्षमता भी रखता है। यहां विकसित हो रहा आधुनिक कार्गो नेटवर्क निर्यात और आयात दोनों को नई गति देगा। साथ ही भारत का पहला एकीकृत एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल) केंद्र भी यहां स्थापित किया जा रहा है। अभी तक भारतीय एयरलाइंस को विमानों के रखरखाव के लिए सिंगापुर या दुबई जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। जेवर में यह सुविधा विकसित होने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी, विमानन उद्योग को मजबूती मिलेगी और भविष्य में विदेशी एयरलाइंस भी यहां सेवाएं लेने के लिए आ सकती हैं।

कृषि और रोजगार को मिलेगा बड़ा लाभ

■ जेवर हवाई अड्डा केवल उद्योगों के लिए ही नहीं, बल्कि किसानों के लिए भी नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। प्रदेश के फल, सब्जियां, दुग्ध उत्पाद और सजावटी फूल अब कम समय में सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकेंगे। इससे किसानों को बेहतर कीमत मिलने और उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। इसके साथ ही फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, खिलौना पार्क, डाटा सेंटर तथा अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के माध्यम से लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम

■ पिछले कुछ वर्षों में यूपी ने निवेश आकर्षित करने और आधारभूत संरचना विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य को लाखों करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और पूंजीगत व्यय में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, जो भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। इस दृष्टि से जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा केवल एक परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि यूपी की नई आर्थिक पहचान, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और भविष्य की विकास यात्रा का मजबूत आधार बनकर उभर रहा है। यदि योजनाएं निर्धारित गति से आगे बढ़ती रहीं, तो आने वाले वर्षों में यूपी न केवल भारत, बल्कि वैश्विक विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स मानचित्र पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकता है।

सुधारों की दिशा में सार्थक पहल

नागरिक की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती

न्याय व्यवस्था का लक्ष्य-समयबद्ध, तकनीक-सक्षम और पीड़ित-केंद्रित न्याय प्रणाली का निर्माण

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

किसी भी आम नागरिक के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली का अर्थ केवल कानूनों और न्यायालयों तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसका वास्तविक मूल्य इस बात से तय होता है कि उसे न्याय कितनी जल्दी और कितनी निष्पक्षता से मिलता है। जब कोई व्यक्ति अपराध का शिकार होता है तो उसकी पहली अपेक्षा होती है कि उसकी शिकायत तुरंत दर्ज हो, जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो, साक्ष्य सुरक्षित रखे जाएं, गवाहों को समय पर बुलाया जाए और मुकदमे का फैसला अनावश्यक देरी के बिना हो। दुर्भाग्य से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली लंबे समय तक इन अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरी नहीं उतर सकी। वर्षों तक लंबित मुकदमे, जटिल प्रक्रियाएं और विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय की कमी ने न्याय प्रक्रिया को धीमा और आम नागरिक के लिए कठिन बना दिया।

पुरानी व्यवस्था की प्रमुख कमियां

भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था लंबे समय से दोहरी समस्या से जूझती रही है। पहली समस्या थी मामलों के निस्तारण में अत्यधिक विलंब और दूसरी विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का अभाव। पुलिस, अदालत, अभियोजन, फोरेंसिक प्रयोगशालाएं और जेल प्रशासन अलग-अलग व्यवस्था के तहत काम करते रहे, जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान धीमा रहा। कागजी कार्यवाही के बोझ और अलग-अलग प्रक्रियाओं के कारण मामलों का समय पर निपटारा प्रभावित हुआ। परिणामस्वरूप पूरी व्यवस्था पीड़ित-केंद्रित होने के बजाय प्रक्रिया-केंद्रित बनकर रह गई। यही कारण है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 को न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एक जुलाई 2024 से लागू इन नए कानूनों का उद्देश्य केवल पुराने कानूनों को बदलना नहीं, बल्कि आधुनिक, तकनीक-सक्षम और अधिक प्रभावी न्याय प्रणाली स्थापित करना है।

समयबद्ध न्याय की नई व्यवस्था

■ नई न्याय व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए स्पष्ट समय-सीमाओं का निर्धारण है। जांच और न्यायिक कार्यवाही के अलग-अलग चरणों में 45 नई समय-सीमाएं जोड़ी गई हैं, जिससे कुल निर्धारित समय-सीमाओं की संख्या 145 हो गई है। लक्ष्य यह है कि किसी भी आपराधिक मामले की जांच से लेकर अंतिम निर्णय तक की प्रक्रिया तीन वर्ष के भीतर पूरी हो सके। यह केवल घोषणा भर नहीं है, बल्कि इसे तकनीकी निगरानी प्रणाली से जोड़ा गया है। जांच अधिकारियों को समय-समय पर स्वचालित अलर्ट मिलते हैं, जिससे आरोप-पत्र समय पर दाखिल हो सके और किसी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो।

तकनीक से बढ़ी पारदर्शिता और जवाबदेही

■ नई व्यवस्था में तकनीक केवल सुविधा का माध्यम नहीं, बल्कि पूरी न्याय प्रक्रिया का आधार बन गई है। न्यायालयों के केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम में भी समय-सीमाओं की निगरानी की व्यवस्था विकसित की जा रही है, ताकि प्रत्येक स्तर पर प्रगति पर नजर रखी जा सके। इसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देने लगा है। निर्धारित समय के भीतर आरोप-पत्र दाखिल करने की दर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब समय-सीमा और तकनीक का प्रभावी समन्वय होता है, तो न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और भरोसेमंद बनती है।

डिजिटल न्याय व्यवस्था की ओर बड़ा कदम

■ नई आपराधिक न्याय प्रणाली का दूसरा महत्वपूर्ण आधार व्यापक डिजिटलीकरण है। अब ई-एफआईआर, जीरो एफआईआर, ई-साक्ष्य, ई-समन, ई-फोरेंसिक, ई-प्रिजंस, ई-प्रॉसिक्यूशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई तथा मेडिको-लीगल एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसी अनेक सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे कागजी कार्यवाही कम होगी, सूचनाओं का आदान-प्रदान तेज होगा और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी। डिजिटल प्रमाणित दस्तावेजों के उपयोग से त्रुटियों की संभावना भी कम होगी और मामलों के निस्तारण में गति आएगी।

एकीकृत प्रणाली से बढ़ेगा समन्वय

■ सुधारों का एक महत्वपूर्ण पहलू इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) का विस्तार है। 'वन डाटा, वन एंट्री' की अवधारणा पर आधारित यह व्यवस्था पुलिस, न्यायालय, अभियोजन, फोरेंसिक संस्थानों और जेल प्रशासन को एक साझा डिजिटल मंच पर जोड़ती है। इससे एक ही जानकारी को बार-बार दर्ज करने की आवश्यकता समाप्त होगी तथा पुलिस और अदालतों के बीच एफआईआर एवं आरोप-पत्र का लगभग वास्तविक समय में आदान-प्रदान संभव होगा। इससे न केवल काम का दोहराव कम होगा, बल्कि डेटा की शुद्धता भी बढ़ेगी और न्यायिक कार्रवाई अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी।

वैज्ञानिक जांच को मिलेगा बढ़ावा

■ भारतीय न्याय व्यवस्था में साक्ष्यों की गुणवत्ता हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सात वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले मामलों में फोरेंसिक विशेषज्ञ की भागीदारी अनिवार्य की गई है। इसके लिए देशभर में 700 से अधिक मोबाइल फोरेंसिक वैन तैनात की गई हैं और भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे घटनास्थल पर ही वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र किए जा सकेंगे, जिससे जांच की गुणवत्ता बेहतर होगी और अदालतों में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पिछले दो वर्षों में फोरेंसिक मामलों के निस्तारण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि इसी दिशा में सकारात्मक संकेत देती है।

सफल क्रियान्वयन ही असली परीक्षा

■ किसी भी बड़े कानूनी सुधार की सफलता केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन से तय होती है। नई आपराधिक न्याय व्यवस्था की सफलता भी केंद्र और राज्य सरकारों, पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन, फोरेंसिक संस्थानों और जेल प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर निर्भर करेगी। आज देश के पास आधुनिक कानूनी ढांचा, डिजिटल तकनीक और संस्थागत इच्छाशक्ति—तीनों उपलब्ध हैं। आवश्यकता केवल निरंतर प्रतिबद्धता और प्रभावी कार्यान्वयन की है। यदि इन सुधारों को पूरी गंभीरता से लागू किया गया, तो भारत की न्याय प्रणाली अधिक पारदर्शी, समयबद्ध, भरोसेमंद और नागरिक-केंद्रित बन सकेगी। यही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी आवश्यकता और आम नागरिक की सबसे महत्वपूर्ण अपेक्षा भी है।

प्रेरक प्रसंग

मिट्टी का सम्मान

बार-बार लोगों के पैरों तले रौंदी जाने वाली मिट्टी एक दिन अपने भाग्य पर रो पड़ी। उसने दुखी होकर कहा, "मैं कितनी अभागी हूं। हर कोई मुझे ठोकर मारता है, कोई सम्मान नहीं देता। जबकि मेरे ही भीतर से जन्म लेने वाले फूलों को लोग सिर-आंखों पर बिठाते हैं। उनकी मालाएं बनती हैं, भगवान के चरणों में चढ़ाई जाती हैं और महिलाएं उन्हें अपने बालों में सजाकर गर्व महसूस करती हैं। काश! मुझे भी ऐसा सम्मान मिलता।" मिट्टी की यह व्यथा पास ही खड़े एक कुंभकार ने सुन ली। वह मुस्कुराते हुए बोला, "मिट्टी बहन, यदि तुम सचमुच सम्मान पाना चाहती हो, तो मैं तुम्हें वह सम्मान दिला सकता हूं। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी।" मिट्टी ने बिना देर किए कहा, "मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बस मुझे इस अपमान भरे जीवन से निकाल लो।" कुंभकार ने जमीन खोदकर मिट्टी को बाहर निकाला, गधे पर लादकर अपने घर ले आया और पानी में भिगोकर कई दिनों तक गीला रखा। इसके बाद उसने अपने पैरों से उसे बार-बार रौंदा। मिट्टी दर्द से कराह उठी और बोली, "भाई, तुम तो मुझे और अधिक कष्ट दे रहे हो। आखिर सम्मान कब मिलेगा?" कुंभकार ने शांत स्वर में कहा, "धैर्य रखो बहन। हर बड़ा सम्मान कठिन परीक्षा के बाद ही मिलता है। जो कष्ट तुम आज सह रही हो, वही तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाएगा।" मिट्टी ने चुपचाप सब सहना स्वीकार कर लिया। फिर कुंभकार ने उसे चाक पर चढ़ाया। घूमते हुए चाक पर उसने मिट्टी को सुंदर घड़े का आकार दिया। इसके बाद उसे तेज धूप में सुखाया गया। लगातार कष्ट झेलते-झेलते मिट्टी का धैर्य टूटने लगा।

■ तब कुंभकार ने कहा कि अब बस एक अंतिम परीक्षा बाकी है-अग्नि-परीक्षा। यदि इसमें भी सफल हो गई, तो लोग तुम्हें सिर पर उठाकर चलेंगे। जैसे माता सीता ने अग्नि-परीक्षा देकर अपना गौरव सिद्ध किया था, वैसे ही तुम्हें भी सम्मान मिलेगा।" मिट्टी ने साहस जुटाया और भट्ठी की भीषण आग को भी सह लिया।

■ जब वह तपकर मजबूत और सुंदर घड़ा बनकर बाहर निकली, तो उसका रूप ही बदल चुका था। अब वही मिट्टी, जिसे लोग पैरों तले रौंदते थे, महिलाओं के सिर पर सजे घड़े के रूप में सम्मान के साथ उठाई जाने लगी। हर कोई उसकी उपयोगिता और सुंदरता की प्रशंसा करने लगा।

■ उस दिन मिट्टी को समझ में आ गया कि जीवन में सम्मान और सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलते। जो व्यक्ति धैर्य, मेहनत और कठिनाइयों की अग्नि-परीक्षा को पार कर लेता है, वही समाज में सम्मान का पात्र बनता है। शिक्षा : जीवन में सम्मान, सफलता और ऊंचा स्थान पाने के लिए कठिन परिश्रम, धैर्य और संघर्ष की अग्नि-परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है।

राशिफल

मेष- निवेश के सुखद परिणाम आएंगे। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। किसी बड़ी बाधा के दूर होने से प्रसन्नता रहेगी। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। पुराना रोग उभर सकता है। विवाद से क्लेश संभव है।

वृषभ-आय बनी रहेगी। व्यस्तता रहेगी। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। दूसरों से अपेक्षा पूर्ण नहीं होने से खिन्नता रहेगी। कार्य में विलंब होगा। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी।

मिथुन- व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। भाग्य का साथ रहेगा। व्यापार में वृद्धि के योग हैं। निवेश शुभ रहेगा। आय होगी। प्रमाद न करें। पुराने शत्रु परेशान कर सकते हैं। थकान व कमजोरी रह सकती है।

कर्क-कारोबार में वृद्धि होगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। नए व्यापारिक अनुबंध होंगे। धनार्जन होगा। लंबे समय से रुके कार्यों में गति आएगी। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें।

सिंह- कोर्ट व कचहरी के कार्य अनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। परिवार के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा। आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। कारोबार अच्छा चलेगा। नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्नता रहेंगे। किसी व्यक्ति से बेवजह विवाद हो सकता है।

कन्या- धनलाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आय में निश्चितता होगी। ऐश्वर्य पर व्यय होगा। वाहन व मशीनरी आदि के प्रयोग में सावधानी रखें, विशेषकर स्त्रियां रसोई में ध्यान रखें। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। भाइयों का सहयोग मिलेगा। प्रसन्नता बनी रहेगी।

तुला-कोर्ट व कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे। जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा। सुख के साधन जुटेंगे। कारोबार में वृद्धि होगी। निवेशादि शुभ रहेंगे। नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे। स्त्री पक्ष से लाभ होगा। अज्ञात भय रहेगा। शत्रु परास्त होंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे।

वृश्चिक- आय में वृद्धि होगी। भूमि व भवन संबंधी योजना बनेगी। कोई बड़ा लाभ हो सकता है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। भाग्य बेहद अनुकूल है, लाभ लें। चोट व रोग से बचें। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी।

धनु- भागदौड़ रहेगी। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। प्रसन्नता रहेगी। किसी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जल्दबाजी व लापरवाही न करें। अज्ञात भय सताएगा।

मकर- आज लेन-देन में विशेष सावधानी रखें। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। दु:खद समाचार मिल सकता है। किसी व्यक्ति से बेवजह विवाद हो सकता है। व्यर्थ भागदौड़ होगी। कार्य में विलंब होगा। चिंता तथा तनाव रहेंगे। आय में निश्चितता रहेगी।

कुंभ- पराक्रम बढ़ेगा। आय में वृद्धि होगी। पराक्रम बढ़ेगा। किसी बड़े काम को करने में रुझान रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रशंसा प्राप्त होगी। शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड से लाभ होगा। चोट व रोग से बचें। सुख के साधन जुटेंगे। घर में तनाव रह सकता है।

मीन-आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विवेक से कार्य करें। विरोधी सक्रिय रहेंगे। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। घर में मेहमानों का आगमन होगा। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। नौकरी में चैन रहेगा। आय में वृद्धि होगी। प्रमाद न करें।

भारत-जापान की मेगा डील!

डिफेंस से फार्मा तक हुए बड़े समझौते, जानें इंडो-पैसिफिक में अब कैसे होगा बदलाव?

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

भारत और जापान के बीच कूटनीतिक संबंधों ने आज एक नया और भावुक इतिहास रच दिया है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचीं, जहां हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान न केवल दोनों देशों के बीच सामरिक रिश्तों को मजबूती मिली, बल्कि पीएम मोदी द्वारा जापानी पीएम को 'छोटी बहन' कहकर संबोधित करने ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबका ध्यान खींचा है। इस बैठक से पहले जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।

दोनों देशों में रिश्तों का नया अध्याय

संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद आत्मीयता के साथ सनाए ताकाइची का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ताकाइची, मेरी छोटी बहन, भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए उनकी पहली भारत यात्रा पर मुझे बेहद खुशी है। प्रधानमंत्री ने ताकाइची को एक दूरदर्शी नेता बताया और कहा कि उनके नेतृत्व में भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी अब एक नए और सुनहरे अध्याय में प्रवेश कर रही है।

फार्मा और डिफेंस सेक्टर में हुए बड़े समझौते

हैदराबाद हाउस में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु आर्थिक और सामरिक सहयोग रहा। दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और जापान ने फार्मास्युटिकल, रक्षा, उन्नत तकनीक और निवेश जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन (MoC) पर हस्ताक्षर किए। विशेष रूप से रक्षा सहयोग को लेकर दोनों देशों ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन को मजबूती मिलेगी।

साझा बौद्ध विरासत का जिक्र

पीएम मोदी ने सनाए ताकाइची के गृह प्रांत 'नारा' का जिक्र करते हुए इसे भारत और जापान की साझा बौद्ध विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बताया। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले कई दशकों में ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत के विकास की यात्रा में एक विश्वसनीय भागीदार की भूमिका निभाई है।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को मिलेगा लाभ

बैठक के दौरान भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), और सप्लाई चेन जैसे उभरते क्षेत्रों पर भी गहन चर्चा हुई। पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में यह साझेदारी न केवल दोनों देशों के विकास के लिए, बल्कि पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक उथल-पुथल के इस दौर में भारत और जापान का आपसी विश्वास सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है।

तमिलनाडु में विजय की सरकार गिराने की कोशिश नाकाम

35-35 करोड़ में खरीदे जा रहे थे TVK विधायक; 3 गिरफ्तार

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

तमिलनाडु में हुए सत्ता परिवर्तन के कुछ दिनों बाद ही सीएम जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली टीवीके सरकार को तोड़ने की चर्चाओं का बाजार गरम है। टीवीके के एक विधायक को सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए कथित तौर पर 35 से 50 करोड़ रुपये तक की पेशकश किए जाने के मामला सामने आया है। इस केस में सख्त एक्शन लेते हुए तमिलनाडु पुलिस ने बुधवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य में शुरू हुई सियासी हलचल को देखते हुए मुख्यमंत्री विजय ने बुधवार को चेन्नई में सरकार के सहयोगी दलों के साथ एक इमरजेंसी बैठक की। वहीं, एमके स्टालिन की नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टी डीएमके ने इन आरोपों को नकारते हुए मामले की हाई लेवल जांच की मांग की है।

क्या है यह पूरा मामला?

टीवीके विधायक एन. इलैयाराजा द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप है कि विधानसभा में एक प्रस्तावित एक प्रस्ताव के खिलाफ में वोट के बदले 35 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, थिरुनावुक्कारसु नाम के व्यक्ति ने टीवीके विधायक से संपर्क किया था। उसने खुद को इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज नामक एक राजनीतिक फर्म का सदस्य बताया था। विधायक इलैयाराजा का आरोप है कि जब उनके द्वारा इस ऑफर को ठुकाराया गया, तो आरोपी ने उन्हें और उनके परिवार को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। विधायक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए थिरुनावुक्कारसु और उसके दो साथियों नरेश और त्यागराजन को अरेस्ट कर लिया है।

टीवीके का DMK पर आरोप

तमिलनाडु की राजनीति में उस समय और ज्यादा उबाल आ गया जब टीवीके सरकार में मंत्री निर्मल कुमार ने इस पूरी घटना के पीछे विपक्षी दल डीएमके का हाथ बताया। उन्होंने यह भी कह दिया कि डीएमके के सीनियर लीडर सेंथिल बालाजी पिछले एक महीने से टीवीके के कई विधायकों तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री निर्मला कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सेंथिल बालाजी एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन के साथ मिलकर टीवीके के कई विधायाकों से संपर्क किया था। हमारे विधायकों को 10 से 50 करोड़ रुपए तक का लालच दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पार्टी का एक भी ऐसा विधायक नहीं है, जिससे उन्होंने संपर्क नहीं साधा हो। तमिलनाडु पुलिस के करीबी सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में से एक नरेश डीएमके नेता सेंथिल बालाजी के भाई अशोक कुमार के साथ संपर्क में था। इन दोनों के बीच फोन पर इस इस बात की चर्चा होती थी कि किस विधायक को कितने पैसे का ऑफर देना है।

आरोपों से DMK का इनकार

टीवीके के ओर से लगाए गए इन गंभीर आरोपों को डीएमके ने नकार दिया है। टीवीके पर हमला बोलते हुए डीएमके ने मुख्यमंत्री विजय पर आरोप लगाया है कि वह खुद जनादेश को पलटने का सिस्टमैटिक प्रयास कर रहे हैं। तमिलनाडु के गवर्नर और सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय से शिकायत करते हुए डीएमके ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। डीएमके का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने उनकी पार्टी के दो विधायकों को इस्तीफा देने का लालच दिया है। डीएमके ने हाल ही में एमडीएमके नेता वाइको के उस बयान का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने डीएमके से नाता तोड़कर टीवीके को समर्थन देने का एलान किया था।

पेट्रोल और डीजल के दाम घटेंगे: हरदीप सिंह पुरी

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

अगर सबकुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम घट सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसके संकेत दिए हैं। पुरी ने कहा कि तेल कीमतों के कुछ सप्ताह तक निचले स्तर पर बने रहने पर पेट्रोल-डीजल के दाम में कटौती पर विचार करना उचित होगा। पुरी के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम घटे हैं लेकिन कंपनियां अब भी पश्चिम एशिया संकट के दौरान खरीदे गए कच्चे तेल का ही प्रोसेसिंग कर रही हैं। 30 जून की अवधि तक पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लागत से कम दाम पर बेचने की वजह से पेट्रोलियम कंपनियों को 74,781 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

अप्रैल-मई में खरीदे गए ईंधन की प्रोसेसिंग

दरअसल, कंपनियां ईंधन उत्पादन के लिए कच्चा तेल आमतौर पर कम-से-कम दो महीने पहले खरीदती हैं। ऐसे में वर्तमान में जिस कच्चे तेल का प्रोसेसिंग हो रहा है, वह मुख्य रूप से अप्रैल या मई की शुरुआत में खरीदा गया था जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें काफी ऊंची थीं। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष समाप्त करने को लेकर सहमति बनने के बाद जून के दूसरे पखवाड़े से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आनी शुरू हुई है। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि कंपनियां ईंधन उत्पादन के लिए कच्चा तेल आमतौर पर कम-से-कम दो महीने पहले खरीदती हैं। ऐसे में वर्तमान में जिस कच्चे तेल का प्रोसेसिंग हो रहा है, वह मुख्य रूप से अप्रैल या मई की शुरुआत में खरीदा गया था जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें काफी ऊंची थीं। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष समाप्त करने को लेकर सहमति बनने के बाद जून के दूसरे पखवाड़े से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आनी शुरू हुई है।

कटौती का दौर शुरू

हाल ही में पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के कारण कटौती का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बीते एक जुलाई को विमान ईंधन (एटीएफ) और कॉमर्शियल एलपीजी की कीमतों में कटौती की गई। वहीं, निजी ईंधन खुदरा कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए, जो दो साल से अधिक समय में उसकी पहली कटौती है। अब सरकारी तेल कंपनियों पर हर किसी की निगाहें हैं। यह देखना अहम होगा कि इंडियन ऑयल और एचपी जैसी कंपनियां कब तक पेट्रोल-डीजल के दाम घटाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) का देश के 90 प्रतिशत से अधिक ईंधन बाजार पर नियंत्रण हैं।

राबड़ी देवी ने खाली किया सरकारी बंगला

हिंदमाता नेटवर्क @ पटना

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने गुरुवार को उस सरकारी बंगले को खाली कर दिया, जिसका इस्तेमाल वह दो दशक से अधिक समय से अपने आवास और राष्ट्रीय जनता दल के कैंप कार्यालय के रूप में कर रही थीं। राजद के बिहार में 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के कुछ समय बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने राबड़ी को मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने तथा राजभवन के पास 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला आवंटित किया था। अब राबड़ी लगभग दो किलोमीटर दूर कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी आवास में रहने चली गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 10, सर्कुलर रोड स्थित बंगला पार्टी नेता एवं मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया है।

■ बिहार सरकार ने पिछले साल नवंबर में एक आदेश जारी कर 10, सर्कुलर रोड स्थित बंगले को उपमुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास घोषित कर दिया था। इसके साथ ही राज्य विधान परिषद में विपक्ष की नेता होने के नाते राबड़ी को दूसरा सरकारी बंगला आवंटित किया गया था। राबड़ी ने उन्हें आवंटित 39, हार्डिंग रोड स्थित बंगले में जाने से इनकार कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह बंगला 10, सर्कुलर रोड स्थित बंगले की तुलना में छोटा है और इसे राजनीतिक दृष्टि से 'अशुभ' माना जाता है, क्योंकि यहां अतीत में रहने वाले सभी प्रमुख नेताओं का सियासी दबदबा बाद में घट गया। पिछले महीने भवन निर्माण विभाग ने नया आदेश जारी कर राबड़ी देवी को 39, हार्डिंग रोड स्थित आवास में स्थानांतरित होने और 29 जून तक 10, सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करने का निर्देश दिया था।

बंगाल में बदली सियासत की दिशा

ममता युग के बाद शुभेंदु सरकार ने शुरू किया नया राजनीतिक अध्याय

हिंदमाता नेटवर्क @ कोलकाता

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य की राजनीति तेजी से नई दिशा की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि राज्य की राजनीतिक धारा को भी नया मोड़ दिया। इसके साथ ही लगातार 15 वर्षों तक राज्य की सत्ता पर काबिज रही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस के दौर का अंत हुआ और राष्ट्रवाद आधारित नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हुई।

तेजी से लागू किए फैसले

9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य में भाजपा की पहली सरकार का नेतृत्व संभाला। सरकार ने प्रशासन, कानून व्यवस्था, जनकल्याण और शासन व्यवस्था में तेजी से कई बड़े फैसले लागू करने शुरू कर दिए।

राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले

पिछले लगभग 15 वर्षों तक बंगाल की राजनीति का केंद्र ममता बनर्जी रहीं। राज्य सचिवालय नवान्न से लेकर मोहल्लों, सरकारी योजनाओं, पूजा पंडालों और स्थानीय प्रशासन तक उनका प्रभाव साफ दिखाई देता था। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले और अब राज्य में भाजपा के नेतृत्व में नया सत्ता केंद्र स्थापित हो गया है।

यूसीसी की प्रक्रिया शुरू

नई सरकार के कार्यकाल में सबसे बड़ा बदलाव उन मुद्दों पर देखने को मिल रहा है जिन्हें भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रमुखता से उठाया था। सरकार ने पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में विधायी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में सभी समुदायों के लिए समान कानून लागू करना बताया गया है।

धर्मांतरण पर रोक आवश्यक

इसके अलावा सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की भी घोषणा की है। सरकार का कहना है कि यह कानून जबरन या दबाव में कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए आवश्यक है। वहीं, विपक्ष का आरोप है कि इस तरह के कानून संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत नागरिकों को मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ हैं। करीब दो महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में हुए इन बड़े बदलावों ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता युग के बाद बंगाल अब एक नए वैचारिक और प्रशासनिक दौर में प्रवेश कर चुका है।

राम मंदिर चढ़ावा 'चोरी' मामला: आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस ने 24 घंटे की रिमांड पर लिया

हिंदमाता नेटवर्क @ अयोध्या

अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ला को आगे की पूछताछ के लिए गुरुवार को 24 घंटे की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि राम मंदिर में चढ़ावे की रकम की गिनती का काम करने वाले शुक्ला को अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 24 घंटे की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

■ सूत्रों के मुताबिक, शुक्ला से हिरासत में पूछताछ के जरिए जांचकर्ताओं को चंदे के कथित हेरफेर की जांच करने, धन के लेन-देन का पता लगाने और मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में मदद मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान मिली नकदी में शुक्ला के पास से 20.39 लाख रुपए बरामद किए गए थे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अन्य आरोपियों करुणेश पांडे से 18.07 लाख रुपए, अनुकल्प मिश्रा से 16.82 लाख रुपये, लवकुश मिश्रा से 14.25 लाख रुपए, रमाशंकर मिश्रा से 7.32 लाख रुपए और रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू से एक लाख रुपए की बरामदगी हुई थी।

■ सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने जांच के दौरान लगभग 11 ग्राम सोना, करीब 375 ग्राम चांदी और 1,121 अमेरिकी डॉलर भी बरामद किए थे। सूत्रों के मुताबिक, इससे पहले एक अहम घटनाक्रम में जांचकर्ताओं ने अयोध्या के एक योग केंद्र से 'रामराज्य कोष' नाम का दान पात्र बरामद किया था, जिस पर क्यूआर कोड लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि शुक्ला लगभग एक दशक से इसी केंद्र में रह रहा था। राम मंदिर में दान और चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सात जून को सामने आया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

महुआ मोइत्रा पर सरेआम फेंके गए अंडे, लगे चोर के नारे...

कल सरकार गई तो क्या होगा?: अखिलेश यादव

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर कथित रूप से अंडे फेंके जाने की घटना की निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक हिंसा का माहौल पैदा का आरोप लगाया। लोकसभा में 37 सांसदों वाली सपा के अध्यक्ष यादव ने इस घटना को अत्यंत निंदनीय बताया और न्यायपालिका तथा लोकसभा अध्यक्ष से इसका तत्काल संज्ञान लेने की मांग की। महुआ मोइत्रा को कथित तौर पर उस समय भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा, जब वह पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के दौरे पर थीं। आरोप है कि इस दौरान उन पर अंडे फेंके गए।

कल सरकार जाने के बाद क्या होगा?

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने शासन वाले राज्यों में सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का विषैला वातावरण बना रही है तथा पुलिस का राजनीतिकरण कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि इस नकारात्मक-प्रहारात्मक व्यवहार से पूरे देश की जनता बेहद नाराज और आक्रोशित है। यहां तक कि भाजपा के अपने नेता और कार्यकर्ता तक इस तरह के हिंसक हमलों के खिलाफ हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आज जहां उनकी सरकारें नहीं हैं, वहां भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों के ऊपर अगर ऐसा प्राणघातक हमला होना शुरू हो गया तो क्या होगा या फिर कल को उनकी सरकार जाने के बाद क्या होगा।

दिग्गज नेता तो बच जाएंगे, आम कार्यकर्ता पिटेंगे

यादव ने कहा कि भाजपा के बड़े नेता तो सुरक्षा घेरे में खुद को बचा लेंगे लेकिन आम कार्यकर्ता को सड़क पर जनाक्रोश का शिकार होने के लिए छोड़ देंगे। उन्होंने न्यायपालिका और लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की। उन्होंने इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया। तृणमूल मोइत्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पार्टी विधायक अलीफा अहमद के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर अंडे फेंके और उनके खिलाफ नारेबाजी की।

बंगाल में सरकार बदलते ही चरमराई कानून-व्यवस्था

मोइत्रा कालीगंज के पलाशी में अहमद के घर पर तृणमूल की बैठक में शामिल होने गई थीं, तभी बाहर प्रदर्शनकारियों का एक समूह जमा हो गया और वापस जाओ के नारे लगाने लगा। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने अंडे भी फेंके और चोर के नारे लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सरकार बदलने के बाद कानून-व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। अब भाजपा ने मुझ पर हमला करने की साजिश रची है। ये कोई आम लोग नहीं हैं, ये भाजपा कार्यकर्ता हैं।

हिंदमाता एंकर: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान- AI को बताया 'विनाशकारी जहर'

न्याय प्रणाली में हर स्तर पर इंसानी दिमाग जरूरी

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने AI के बढ़ते दुरुपयोग पर बेहद गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई दौरान अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अक का गलत प्रयोग तकनीकी उपकरणों पर वकीलों और प्रोफेशनल्स की अत्यधिक निर्भरता बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। इसी के साथ कोर्ट ने साफ किया है कि न्याय की प्रक्रिया में हर मोड़ पर मानवीय समझ और नियंत्रण का होना जरुरी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

फर्जी एआई कंटेंट के आधार पर आया था फैसला

जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरा मामला NCLT के एक फैसले से जुड़ा है, जो Essel Inraprojects की दिवालियापन प्रक्रिया को लेकर था। इस मामले में कोर्ट में AI के जरिए फेक उदारहण पेश किए गए, जो असल में कभी हुए ही नहीं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी के कारण न्याय की प्रामाणिकता से समझौता नहीं किया जा सकता।

भोपाल गैस त्रासदी की जहरीली गैस से की तुलना

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में AI से बनाई गई फेक साम्रगी की तुलना विनाशकारी और जहरीली गैस 'मिथाइल आइसोसाइनेट' से की है, जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी) से कर दी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा

कानूनी बहसों में एआई द्वारा तैयार किए गए फर्जी, काल्पनिक और झूठे उदाहरणों का इस्तेमाल करना न्याय के क्षेत्र में 'मिथाइल आइसोसाइनेट' गैस छोड़ने जैसा है। यह एक ऐसा अदृश्य और कपटी खतरा है, जो न्याय प्रणाली को भीतर से खोखला कर देता है। जब तक कोई इस धोखे को पकड़ पाता है, तब तक यह न केवल पूरी न्यायिक प्रक्रिया को दूषित कर चुका होता है, बल्कि अदालती फैसले की आत्मा को भी नष्ट कर देता है।

योगी सरकार का बड़ा फैसला! यूपी में नहीं बढ़ेंगी बिजली की दरें

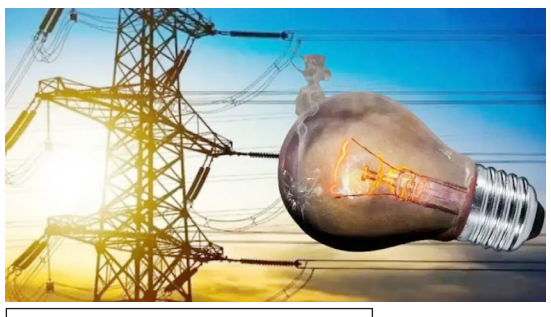

हिंदमाता नेटवर्क @ लखनऊ

उत्तर प्रदेश के करीब 3.70 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि राज्य में मौजूदा बिजली टैरिफ ही लागू रहेगा। इसके साथ ही नोएडा के उपभोक्ताओं को मिलने वाली 10 प्रतिशत बिजली दर छूट (रिबेट) भी पहले की तरह जारी रहेगी। इस फैसले से घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में बड़ी राहत मिलेगी।

लगातार सातवें साल स्थिर रहीं बिजली दरें

आयोग के इस फैसले के साथ उत्तर प्रदेश लगातार सात वर्षों तक बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पिछले सात वर्षों से प्रदेश में बिजली की टैरिफ दरें स्थिर रखी गई हैं, जिससे करोड़ों उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ा है। ऐसे समय में जब देश के कई राज्यों में बिजली की दरों में संशोधन कर उन्हें बढ़ाया गया है, उत्तर प्रदेश में दरें यथावत रखना आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि स्थिर बिजली दरों की नीति से आम लोगों के साथ-साथ छोटे कारोबारियों और उद्योगों को भी लाभ मिला है।

ईवी चार्जिंग स्टेशनों को मिलेगा विशेष फायदा

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोग ने एक और अहम फैसला लिया है। अब प्रदेश में ईवी चार्जिंग स्टेशनों को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली की खपत पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, चार्जिंग लागत कम होगी और स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही प्रदेश में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को भी गति मिलने की उम्मीद है।

नोएडा के उपभोक्ताओं को पहले की तरह मिलेगा 10% रिबेट

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने नोएडा क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली 10 प्रतिशत बिजली दर छूट को भी जारी रखने का निर्णय लिया है। इस फैसले से नोएडा के लाखों घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ता पहले की तरह रियायती दरों पर बिजली का लाभ उठाते रहेंगे। आयोग के इस निर्णय से नोएडा के उपभोक्ताओं को किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा।

यूपी का विधानसभा चुनाव सितंबर में करा दें, हम तैयार हैं..

अखिलेश यादव का बड़ा बयान

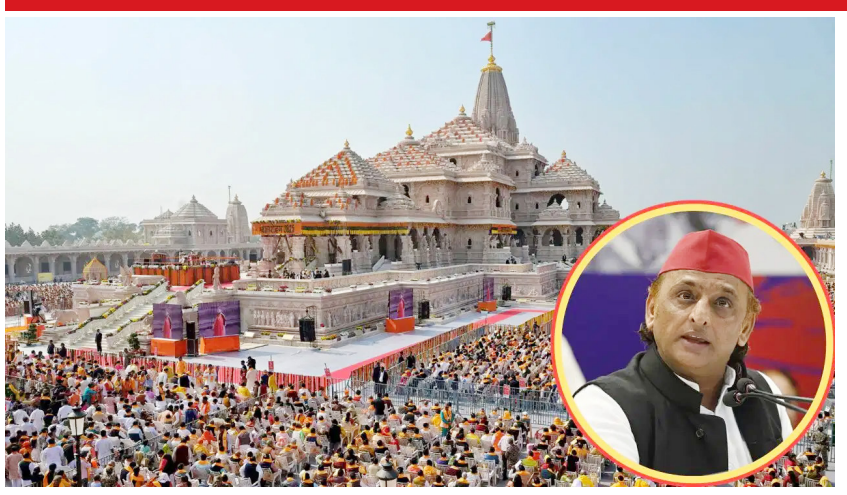

हिंदमाता नेटवर्क @ लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। कन्नौज सांसद ने कहा है कि जो लोग नवंबर में चुनाव करवाना चाहते थे, सितंबर में करवा दें। हमलोग तैयार हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि आज न्याय के लिए लोग कहीं भी भटक लें, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस बार बीजेपी को न चंदा मिलेगा, न दान, न चढ़ावा और न ही वोट। उन्होंने कहा कि मयार्दा का पहला नाम प्रभु श्रीराम हैं और दूसरा नाम संविधान है। उनके मुताबिक पहले आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया और अब संविधान को दबाने का काम हो रहा है, जिससे आस्था, मयार्दा और श्रद्धा तीनों को ठेस पहुंची है।

चोरी बीजेपी की प्रैक्टिस- अखिलेश

राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित घोटाले का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चोरी बीजेपी की "प्रैक्टिस" बन चुकी है और इस बार स्वयं प्रभु श्रीराम ने उनकी पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मयार्दा पुरुषोत्तम राम के नाम पर चढ़े चढ़ावे का सही आंकड़ा सामने आए तो रकम बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि गुप्त दान का भी कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंततः प्रभु श्रीराम ही इसका हिसाब-किताब करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, थाना-पुलिस भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं। इस बार भाजपा को चंदा, दान, चढ़ावा और वोट नहीं मिलने वाला है। इन्होंने संविधान, आस्था, मयार्दा और श्रद्धा को डगा दिया है। हमें उम्मीद है कि प्रभु श्री राम के चढ़ावे को लेकर जो चचार्एं बनी है, वह सच्चाई अभी और बाहर आएगी।

शॉर्ट स्टोरी

पटना मेट्रो को मिला नया स्टेशन, सीएम सम्राट चौधरी ने किया उद्घाटन

हिंदमाता नेटवर्क @ पटना

बिहार में पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के प्रायोरिटी कॉरिडोर के तहत गुरुवार को एक नया मेट्रो स्टेशन शुरू किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मलाही पकड़ी चौक मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान वे सोशल मीडिया पर लाइव भी आए, जहां उन्हें रिबन काटते और स्टेशन का मुआयना करते देखा गया। गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना मेट्रो के मलाही पकड़ी चौक स्टेशन को आम लोगों के लिए शुरू किया। इस मौके पर वे सोशल मीडिया पर लाइव आए और लोगों को स्टेशन दिखाया। वीडियो में सम्राट चौधरी रिबन काटते और स्टेशन के अंदर घूमते हुए नजर आए। इस कार्यक्रम में उनके साथ दोनों उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा शहरी विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा और कई बड़े अधिकारी भी साथ में दिखे। उद्घाटन के बाद सम्राट चौधरी और बाकी नेताओं ने मेट्रो ट्रेन में सफर भी किया। सभी नेता एक साथ ट्रेन में बैठकर स्टेशन से यात्रा करते नजर आए। बता दें कि पटना मेट्रो का पहला चरण पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ था। उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया था। पहले चरण के तहत करीब 3.6 किलोमीटर लंबा प्रायोरिटी कॉरिडोर शुरू हुआ था, जो इंटर स्टेट बस टर्मिनल यानी आईएसबीटी से भूतनाथ स्टेशन तक चलता है। अब इसी कॉरिडोर में मलाही पकड़ी चौक स्टेशन को नया जोड़ा गया है। इससे पटना मेट्रो के इस रूट पर अब यात्रियों के लिए एक और सुविधा बढ़ गई है। लोग अब इस नए स्टेशन से भी मेट्रो पकड़ सकेंगे।

लवकुश मिश्रा ने चढ़ावा चोरी के मामले में कबूली ये बातें

500 रुपए के 2850 नोट बरामद

हिंदमाता नेटवर्क @ अयोध्या

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की हेराफेरी और गबन मामले की जांच में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस के अनुसार लवकुश मिश्रा से पूछताछ की गई है। इस पूछताछ के दस्तावेज एबीपी न्यूज के पास उपलब्ध हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी लवकुश ने स्वीकार किया कि मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे की धनराशि की गणना के दौरान चोरी, गबन और भ्रष्टाचार किया गया था। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने यह भी बताया कि उसके पास बची हुई रकम ट्रस्ट को वापस की जानी थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की निशानदेही पर गवाहों की मौजूदगी में एक स्थान से 500 रुपये के 2,850 नोट, यानी कुल 14 लाख 25 हजार रुपये बरामद किए गए।

दयाशंकर सिंह ने क्या कहा?

बरामदगी के दस्तावेज ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब एसआईटी की जांच के लिए 15 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष हुआ और लाखों लोगों ने अपना योगदान दिया, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच पूरी पारदर्शिता और व्यवस्थित तरीके से हो, इसलिए एसआईटी को अतिरिक्त समय दिया गया है।

संभल में 101 करोड़ की सरकारी जमीन का महाघोटाला

शाहजहांपुर के सहायक नगर आयुक्त गिरफ्तार, 60 साल बाद खुला राज

हिंदमाता नेटवर्क @ संभल

यूपी की संभल पुलिस ने संभल-मुरादाबाद स्टेट हाईवे के किनारे स्थित 101 करोड़ रुपये की 38 बीघा सरकारी जमीन के घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शाहजहांपुर में तैनात सहायक नगर आयुक्त राजकुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। राजकुमार गुप्ता ने साल 2013 में संभल नगर पालिका के ईओ पद पर रहते हुए हाईकोर्ट में पैरवी करने से इनकार कर दिया था। इस महाघोटाले का पदार्फाश डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण बिश्नोई द्वारा जमीन की पैमाइश कराने के बाद हुआ है। लेखपाल स्पर्श गुप्ता की तहरीर पर तत्कालीन ईओ राजकुमार गुप्ता सहित 31 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

1967 से शुरू हुआ जालसाजी का खेल

यह पूरा मामला साल 1967 में शुरू हुआ था जब नगर पालिका ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर फर्जी तरीके से तथाकथित पट्टा कर दिया था। इसके बाद 1991 से 2005 तक अपर तहसीलदार और एडीएम कोर्ट की सुनवाई में इस जमीन को सरकारी माना गया। खेल तब बदला जब 2008 में तत्कालीन डीडीसी खेम सिंह खड़क ने फर्जी पट्टा धारक भू-माफियाओं के पक्ष में आदेश जारी कर कब्जा दे दिया।

पैरवी से पीछे हटे तत्कालीन ईओ

डीडीसी के इस गलत आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। आरोप है कि साल 2013 में संभल में तैनात रहे तत्कालीन ईओ राजकुमार गुप्ता ने भू-माफियाओं और डीडीसी खेम सिंह खड़क से मिलीभगत की। उन्होंने हाईकोर्ट में नोट प्रेस करके नगर पालिका की तरफ से मामले की पैरवी करने से साफ इनकार कर दिया था।

खतौनी में फिर दर्ज हुआ सरकार का नाम

प्रशासनिक सख्ती के बाद चार दिन पहले डीडीसी कोर्ट के आदेश पर खतौनी से निजी भू-स्वामियों का नाम हटा दिया गया। अब 60 साल बाद इस 101 करोड़ रुपये की बेशकीमती जमीन को दोबारा राज्य सरकार के नाम दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब गिरफ्तार किए गए आरोपी राजकुमार गुप्ता से आगे की पूछताछ कर रही है।

सांवले रंग और लगातार रिजेक्शन से टूटे रिश्ते, युवती ने की आत्महत्या

हिंदमाता नेटवर्क @ मुजफ्फरपुर

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक बेहद भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने समाज में रंग-रूप को लेकर बनी धारणाओं पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। गायघाट थाना क्षेत्र के मकरंदपुर गांव में 22 साल की अंशु कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि शादी के लिए लगातार रिश्ते टूटने से वह लंबे समय से मानसिक तनाव में थी। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है, जबकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। मृतका की पहचान पीतांबर कुमार की पुत्री अंशु कुमारी के रूप में हुई है। परिवार के अनुसार, पिछले करीब तीन साल से उसकी शादी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इस दौरान 10 से अधिक परिवार उसे देखने आए, लेकिन किसी भी जगह रिश्ता तय नहीं हो सका। परिजनों का दावा है कि अंशु को लगता था कि उसके सांवले रंग की वजह से रिश्ते आगे नहीं बढ़ रहे हैं। धीरे-धीरे यह बात उसके मन पर गहरा असर डालने लगी और वह खुद को लेकर हीन भावना महसूस करने लगी थी। परिवार ने बताया कि बुधवार को भी एक परिवार अंशु को देखने आने वाला था। मंगलवार रात वह बिना खाना खाए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने खिड़की से देखा तो उसका शव पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका मिला। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलने पर गायघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) भेज दिया गया। गायघाट थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की ओर से दिए जाने वाले आवेदन के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस हर पहलू की पड़ताल कर रही है और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

चंदा चोरी के आरोपी लवकुश के मकान पर चलेगा बुलडोजर? पत्नी को नोटिस

हिंदमाता नेटवर्क @ अयोध्या

राम मंदिर दान चोरी मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने उसकी पत्नी को अवैध मकान निर्माण को लेकर नोटिस थमा दिया है। प्राधिकरण ने लवकुश की पत्नी को उनके नाम पर बने घर के कथित अनाधिकृत निर्माण पर नोटिस भेजा है। उधर, पुलिस ने चंदा चोरी मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। यह जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी है। पीटीआई के मुताबिक, एडीए (अयोध्या विकास प्राधिकरण) सूत्रों के मुताबिक, सोहावल तहसील के बनवीरपुर गांव में लवकुश के मकान का निर्माण चल रहा है। मकान वाली जमीन लवकुश की पत्नी सुप्रिया के नाम पर खरीदी गई थी। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि प्राधिकरण से जरूरी अनुमोदन लिए बिना निर्माण किया गया है। वहीं, पुलिस सूत्रों ने कहा कि जांचकर्ताओं ने बुधवार को लवकुश के आवास की भी तलाशी ली थी। इतना ही नहीं उसके परिवार के सदस्यों से पूछताछ भी की थी।

अविनाश पर कसेगा पुलिस का कड़ा शिकंजा!

इस बीच पुलिस सूत्रों ने संकेत दिया कि जांचकर्ता चंदा चोरी मामले में आरोपी आरोपी अविनाश शुक्ला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कड़ी कर सकते हैं। इसी के पास से अब तक सबसे ज्यादा कैश मिला है। अविनाश के पास से 20.39 लाख रुपये, करुणेश पांडे से 18.07 लाख रुपये, लवकुश मिश्रा से 14.25 लाख रुपये, अनुकल्प मिश्रा से 16.82 लाख रुपये, रमाशंकर मिश्रा से 7.32 लाख रुपये और रमाशंकर उर्फ टीनू से एक लाख रुपये बरामद हुए हैं।

यहां एक दशक से रह रहा था अविनाश शुक्ला

पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान करीब 11 ग्राम सोना, करीब 375 ग्राम चांदी और 1121 अमेरिकी डॉलर भी बरामद हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि एक अहम बरामदगी में जांचकताओं ने अयोध्या के एक योग केंद्र से पेटीएम क्यूआर कोड वाला रामराज्य कोष लेबल वाला एक दान बॉक्स जब्त किया, जहां अविनाश शुक्ला लगभग एक दशक से रह रहा था। बता दें कि राम मंदिर के दान में कथित गबन सात जून को सामने आया था।

कौशांबी में खुलने जा रही हैं 31 नई फैक्ट्रियां

युवाओं को मिलेगा रोजगार का मौका

हिंदमाता नेटवर्क @ कौशांबी

इस वित्तीय वर्ष में शासन ने जिले में 300 करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य तय किया है। इसके सापेक्ष उद्योग विभाग की ओर से अब तक करीब पौने तीन सौ करोड़ रुपये निवेश के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) कराए गए हैं। कुल 31 निवेशकों द्वारा किए गए एमओयू के माध्यम से 31 इकाइयां स्थापित होंगी। इन इकाइयों में 1360 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा लगभग तीन साल पहले लखनऊ में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था। उसके बाद से प्रत्येक जिले के लिए हर साल निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया जाने लगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले में 300 करोड़ रुपये निवेश कराने का लक्ष्य उद्योग विभाग को दिया गया था। इसके सापेक्ष अब तक करीब 275 करोड़ रुपये के निवेश के लिए निवेशकों द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग-अलग विभागों में किए गए हैं। निवेशकों ने जिन इकाइयों को स्थापित करने में

रुचि दिखाई है, उसमें देवीगंज में अंडर गारमेंट्स, मूरतगंज में ईंट ब्रिक्स, दारानगर में लकड़ी के दरवाजे-खिड़कियां, डेयरी प्रोडक्ट, छह आरओ प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, राइस, आटा, ऑयल मिल, नर्सिंग कॉलेज आदि शामिल हैं। इस साल के अंत तक अधिक से अधिक इकाइयों को धरातल पर उतारने के लिए विभाग की ओर से निवेशकों की हर तरह की अड़चनें दूर कराने मसलन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कराने, नक्शा पास कराने, बैंकों से ऋण की स्वीकृति दिलवाने आदि से संबंधित काम करवाए जा रहे हैं।

सीएम योगी की माईयुवा योजना, बिना गारंटी 5 लाख रुपए तक लोन

युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही सरकार

हिंदमाता नेटवर्क @ लखनऊ

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सबसे बड़ी ताकत युवा आबादी पर विशेष फोकस किया है। सरकार का लक्ष्य हर साल 1 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करना है। इसी उद्देश्य के साथ 10 सालों में 10 लाख आत्मनिर्भर उद्यमियों को तैयार करने की व्यापक योजना पर काम किया जा रहा है। देश में कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वाले अधिकांश युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूंजी जुटाने की होती है। पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था में अक्सर भारी गारंटी या संपत्ति गिरवी रखने जैसी शर्तें होती हैं, जिन्हें पूरा करना किसी युवा या नए उद्यमी के लिए आसान नहीं होता। माईयुवा योजना इसी चुनौती का समाधान पेश करती है।

5 लाख तक ब्याज मुक्त लोन

उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी 21 से 40 साल की आयु के पात्र युवा अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त और बिना गारंटी वाला ऋण ले सकते हैं। इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की गारंटी या संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। सरकार परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान भी देती है, जिससे व्यवसाय शुरू करने का शुरुआती वित्तीय बोझ कम हो जाता है। योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आवेदन उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के यूपीएमएसएमई पोर्टल और आधिकारिक माईयुवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाते हैं।

बिहार में सफर होगा महंगा! लगेगा टोल टैक्स, जानें कितना?

हिंदमाता नेटवर्क @ पटना

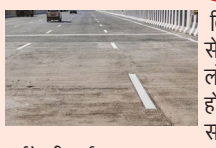

बिहार में सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों की जेब ढीली होने वाली है। राज्य सरकार अब नेशनल हाईवे की तर्ज पर अब राज्य सरकार के स्वामित्व वाले स्टेट हाईवे, बड़े पुलों और बायपास पर भी टोल टैक्स वसूलेगी। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है। यह फैसला सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में लिया गया। नई व्यवस्था के तहत कार, जीप, छोटे व्यावसायिक वाहन, बस, ट्रक और मल्टी-एक्सल वाहनों के लिए अलग-अलग टोल टैक्स की दरें तय की गई हैं। हल्के वाहनों के लिए टोल 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर, जबकि बड़े ट्रकों और भारी वाहनों के लिए 6.65 से 8.10 रुपये प्रति किलोमीटर तक टोल टैक्स निर्धारित किया गया है। हालांकि, फिलहाल किन स्टेट हाईवे और पुलों पर टोल वसूला जाएगा, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। सरकार पहले सड़कों पर वाहनों की आवाजाही की रिपोर्ट तैयार कराएगी। रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन मार्गों पर टोल प्लाजा स्थापित किए जाएंगे। भविष्य में बनने वाले एक्सप्रेसवे को भी इस व्यवस्था में शामिल किए जाने की संभावना है। सरकार ने टोल वसूली को पूरी तरह डिजिटल बनाने की भी तैयारी की है। फास्टैग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रक्रिया के जरिए शुल्क लिया जाएगा। बिना फास्टैग वाले वाहनों को अधिक टोल देना होगा, जबकि ओवरलोडेड वाहनों पर अतिरिक्त जुमार्ना शुल्क लगाया जाएगा। स्थानीय और नियमित यात्रियों के लिए रियायती पास और मल्टीपल ट्रिप जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। नई टोल व्यवस्था कब से लागू होगी, इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है। सड़कों के चयन और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार इसकी अधिसूचना जारी करेगी। फिलहाल कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य में टोलवसूली लागू करने की दिशा में औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है।

हिंदमाता एंकरः सहारनपुर की रहनेवाली एक महिला ने अपनी ही बेटी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है

मां पहुंची थाने, अफसर बेटी पर 15 लाख और जमीन हड़पने का केस

हिंदमाता संवाददाता @ सहारनपुर

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली एक महिला ने अपनी ही बेटी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। हापुड़ में तैनात जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) सीमा चौधरी समेत पांच लोगों के खिलाफ सहारनपुर के सरसावा थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मुकदमा सीमा चौधरी की मां मुनेश रानी की शिकायत पर 30 जून को दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि शिकायत की जांच के बाद प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर केस दर्ज किया गया है और पूरे मामले की विवेचना की जा रही है। एफआईआर में जिला पूर्ति अधिकारी सीमा चौधरी के अलावा संजीव कुमार, गंभीर, राजेंद्र राणा और नरेश कुमार को भी नामजद किया गया है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपों की जांच की जा रही है और विवेचना के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। मुनेश रानी का आरोप है कि उनकी बेटी सीमा चौधरी ने गाजियाबाद स्थित आईसीआईसीआई बैंक में उनके नाम से बैंक खाता खुलवाया था। हालांकि उस खाते का संचालन वह खुद करती थी। उनका कहना है कि खाते में होने वाले किसी भी लेनदेन की जानकारी उन्हें कभी नहीं दी गई। शिकायत के मुताबिक बिना उनकी जानकारी और अनुमति के उसी खाते में 15 लाख रुपये जमा कराए गए। उन्हें इसकी जानकारी तब मिली जब उनके मोबाइल फोन पर बैंक का संदेश आया। इसके बाद वह बैंक पहुंचीं और खाते की जानकारी ली। वहां उन्हें पता चला कि खाते में 15 लाख रुपये जमा हैं। मुनेश रानी ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी ने अपनी कथित काली कमाई को छिपाने के लिए उनके बैंक खाते का इस्तेमाल किया।

जमीन हड़पने की साजिश का भी आरोप

शिकायत में बैंक खाते के अलावा जमीन से जुड़ा गंभीर आरोप भी लगाया गया है। मुनेश रानी का कहना है कि सीमा चौधरी ने कथित रूप से एक भू-माफिया गिरोह के साथ मिलकर उनकी जमीन हड़पने की साजिश रची। उन्होंने आरोप लगाया कि संजीव कुमार, राजेंद्र राणा, गंभीर और नरेश कुमार के साथ मिलकर 16 सितंबर 2023 की एक फर्जी रसीद तैयार की गई। इस रसीद पर उनके जाली हस्ताक्षर किए गए। मुनेश रानी के अनुसार तहसील प्रशासन से जानकारी मिलने के बाद उन्हें इस कथित साजिश का पता चला। इसके बाद उन्होंने अपने हस्ताक्षरों की जांच कराई। जांच रिपोर्ट में हस्ताक्षर अलग बताए गए, जिससे उन्हें फजीर्वाड़े की आशंका हुई। मुनेश रानी का कहना है कि जब उन्होंने इस पूरे मामले का विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार मिल रही धमकियों के कारण वह डर गईं और मजबूरी में अपनी जमीन देहरादून निवासी नैंसी जोशी के नाम बेचनी पड़ी। मुनेश रानी ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले 13 मई को सरसावा थाने में शिकायत दी थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। एसएसपी के निर्देश के बाद 30 जून को शाम करीब साढ़े चार बजे सीमा चौधरी समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

जांच के बाद दर्ज हुआ मुकदमा

नकुड़ क्षेत्र के सीओ पवन कुमार ने बताया कि मुनेश रानी नाम की महिला की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच कराई गई। जांच में प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने जैसे आरोप सामने आए, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि शिकायत में महिला ने अपनी पुत्री और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप लगाए हैं। फिलहाल पूरे मामले की विवेचना जारी है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला सहारनपुर और हापुड़ दोनों जिलों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

71 साल बाद जागा पाकिस्तान, बेटे के साथ बेटियों को पिता की संपत्ति देने पर लिया बड़ा फैसला

हिंदमाता नेटवर्क @ इस्लामाबाद

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक 71 साल पुराने परिवारिक झगड़े को सुलझाते हुए एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि विरासत एक शरिया और कानूनी हक है। अगर किसी परिवार में उसके मुखिया की मौत हो जाती है, उसकी विरासत परिवार के सदस्यों के साथ महिलाओं को भी मिल जाता है। इसे किसी भी अरेंजमेंट, समाजिक दबाव, फेक बिलिंग एंट्री या फिर पैंतरेबाजी के जरिए बदला नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने इस मामले में 26 जनवरी, 2017 के लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विरासत का हक परिवार के पुरुष सदस्यों की खुशी के लिए दिया जाने वाला कोई तोहफा नहीं है, न ही यह रिवाज, सुविधा या पारिवारिक अच्छाई पर निर्भर कोई छूट है।

साल 1955 से चला आ रहा था विवाद

यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब 1955 में एक प्रॉपर्टी के मालिक रोशन की मौत हो गई। उनके कानूनी वारिसों के हक में 4 अप्रैल 1955 को विरासत म्यूटेशन नंबर 74 दर्ज किया गया था। इसके बाद बिल्कुल उसी दिन म्यूटेशन नंबर 75 भी दर्ज किया गया। इसे मृतक के बेटियों द्वारा कथित तौर पर पिता से विरासत में मिली संपत्ति को अपने दो भाइयों के गिफ्ट डीड यानी तोहफे के आधार देना दर्ज किया गया।

याचिकाकर्ताओं ने अपने भाईयों पर लगाए ये गंभीर आरोप

इस मामले में याचिकाकर्ताओ की तरफ कहा गया कि उनकी तरफ से गिफ्ट डीड के तौर पर ऐसा कोई तोहफा अपने वारिसों को नहीं दिया गया था। म्यूटेशन नंबर 75 को महिला वारिसों को उनके कानूनी हिस्से से वंचित रखने के लिए मंजूरी दी गई थी। प्रापर्टी पर कब्जा पाने के लिए मृतक के बेटों और उनके उत्तराधिकारियों ने इसे एक्सचेंज म्यूटेशन और गिफ्ट डीड के जरिए महिला वारिसों के हिस्से की संपत्ति को भी धोखे से अपने पक्ष में ट्रांसफर करा लिया।

मृतक की बेटियों ने विरासत को लेकर केस किया था दायर

याचिकाकताओं यानी मृतक की बेटियों की तरफ से म्यूटेशन नंबर 75 को गैर कानूनी घोषित करने के लिए केस दायर किया गया था। ट्रायल कोर्ट की तरफ से इस केस को खारिज कर दिया गया था। फिर, अपील कोर्ट और लाहौर हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दो जजों की बेंच ने याचिकाकताओं की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि कानून महिला वारिसों के अधिकारों की रक्षा करने के पक्ष में है। इसलिए म्यूटेशन नंबर 75 को गैर-कानूनी, अमान्य घोषित किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि विरासत के लागू कानून के तहत रोशन की संपत्ति में उनकी बेटियां भी हिस्से की हकदार थीं।

पाकिस्तान में 125 साल पुराने गुरुद्वारे पर चला बुलडोजर

भारत ने शहबाज सरकार को लगाई कड़ी फटकार

हिंदमाता नेटवर्क @ इस्लामाबाद

पड़ोसी देश पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला पंजाब प्रांत के फारूकाबाद का है, जहां 125 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब के एक हिस्से को मलबे में तब्दील कर दिया गया। लाहौर से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित इस पवित्र स्थल पर हुई इस कार्रवाई ने न केवल स्थानीय सिख समुदाय को झकझोर दिया है, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक तनाव भी बढ़ा दिया है।

बिना एनओसी के ढहा दी गई विरासत

शुरूआती जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस ऐतिहासिक ढांचे को किसी सरकारी आदेश पर नहीं, बल्कि एक स्थानीय व्यवसायी की मनमानी के कारण ढहाया गया है। पंजाब सरकार के एक अधिकारी के अनुसार, उक्त व्यवसायी ने संबंधित विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बिना ही इस प्राचीन इमारत को गिराना शुरू कर दिया। सबसे गंभीर बात यह है कि स्थानीय प्रशासन और इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने तब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जब तक कि सिख समुदाय ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू नहीं कर दिया।

धार्मिक असहिष्णुता पर उठते सवाल

भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान में व्याप्त सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक असहिष्णुता के माहौल पर गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों को निशाना बनाया गया है। भारत ने अपील की है कि पाकिस्तान सरकार केवल वादे न करे, बल्कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाए।

भारत ने जताया कड़ा ऐतराज

गुरुद्वारे को गिराए जाने की खबर सामने आते ही भारत सरकार ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटना को बेहद निंदनीय और सोची-समझी बर्बरता करार दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह सिखों के एक सम्मानित धार्मिक स्थल के खिलाफ जानबूझकर की गई कार्रवाई है। भारत ने शहबाज शरीफ सरकार से मांग की है कि इस घिनौनी हरकत के दोषियों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाए और गुरुद्वारे के क्षतिग्रस्त हिस्से का जल्द से जल्द पुनर्निर्माण कराया जाए।

सिख समुदाय ने जताया विरोध

इस घटना के बाद पाकिस्तान के सिख समुदाय में भारी आक्रोश व्याप्त है। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दबाव में आकर पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने मामले का संज्ञान लिया है। स्थिति को संभालने के लिए पंजाब प्रांत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने बुधवार को स्वयं फारूकाबाद का दौरा किया। उन्होंने सिख समुदाय को आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों और उनके पूजा स्थलों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण जल्द कराया जाएगा।

यूएस नेवी का हेलीकॉप्टर अरब सागर में क्रैश

इमरजेंसी वॉटर लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा, एक जवान लापता

हिंदमाता नेटवर्क @ वॉशिंगटन

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अरब सागर से एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है। अमेरिकी नौसेना का एक आधुनिक एमएच-60एस सी हॉक हेलीकॉप्टर बुधवार को इमरजेंसी वॉटर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब यह हेलीकॉप्टर अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस जॉर्ज एच डब्ल्यू। बुश पर तैनात होकर नियमित ऑपरेशन में शामिल था। इस आकस्मिक दुर्घटना ने मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अभियानों के बीच खलबली मचा दी है।

हादसे की जांच शुरू

चूंकि यह इलाका रणनीतिक रूप से काफी संवेदनशील है, इसलिए शुरूआत में हमले की आशंका जताई गई थी। हालांकि, अमेरिकी नौसेना ने स्पष्ट किया है कि यह क्रैश किसी बाहरी हमले या शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की वजह से नहीं हुआ था। वर्तमान में घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच की जा रही है।

बचाव अभियान जारी

हादसे के समय हेलीकॉप्टर में कुल चार जवान सवार थे। अमेरिकी नौसेना द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह घटना 1 जुलाई 2026 को सुबह करीब 3:30 बजे हुई। दुर्घटना के तुरंत बाद शुरू किए गए बचाव अभियान में तीन को घायल अवस्था में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि, एक सैनिक अभी भी लापता है, जिसकी तलाश के लिए नौसेना ने अरब सागर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इलाके में मौजूद अन्य अमेरिकी जहाजों और उपलब्ध संसाधनों को लापता सदस्य की खोज में लगा दिया गया है।

कीव पर रूसी हमले में अब तक 13 की मौत, कई इमारतें मलबे में तब्दील

मेट्रो स्टेशनों में कटी लोगों की रात

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

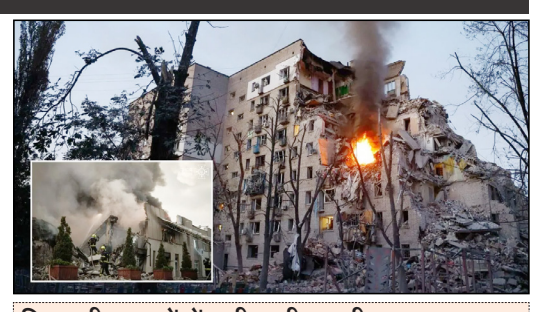

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा तनाव एक बार फिर बेहद हिंसक मोड़ पर पहुंच गया है। गुरुवार की रात रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइलों और घातक ड्रोनों से एक बड़ा हमला किया। इस हमले ने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया और कई घंटों तक जोरदार धमाकों की गूंज सुनाई देती रही। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस हमले में कम से कम 13 लोगों की जान चली गई है और 90 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने यूक्रेन पर इस हमले में 70 से अधिक मिसाइलें दागीं, जिनमें से लगभग आधी बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। इसके साथ ही उन्होंने लगभग 500 ड्रोनों से भी हमला किया।

मेट्रो स्टेशनों में छिपे हजारों लोग

हमले की शुरूआत होते ही यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की और अन्य स्थानीय अधिकारियों ने चेतावनी जारी कर दी थी। रूसी मिसाइलों के डर से हजारों नागरिकों ने अपनी जान बचाने के लिए शहर के विभिन्न मेट्रो स्टेशनों में शरण ली। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने निवासियों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील करते हुए इस हमले को दुश्मन का भीषण हमला करार दिया है।

रिहायशी इलाकों में मची भारी तबाही

कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, शहर में लगभग 30 स्थानों पर भारी नुकसान दर्ज किया गया है। हमले में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। आंतरिक मंत्री इहोर क्लिमेंको ने बताया कि पूरे शहर में कम से कम 20 आवासीय इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। शेवचेनिकोवस्की जिला: यहां एक होटल और दो पांच मंजिला आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। इसके अलावा, घायल हुए लोगों में एक पैरामेडिक भी शामिल है जिसकी हालत बेहद गंभीर है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबीहा ने इस रात को आतंक की रात बताते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अपने सहयोगियों से तत्काल मदद की अपील की है।

पानी के बिना तड़प रहा पाक! एक साल में भारत ने कितना जल रोका?

एक्शन के बाद पहली बार सामने आया डेटा

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

भारत के पानी रोकने के फैसले से पाकिस्तान बुरी तरह परेशान है। पाकिस्तान के सिंधु जल आयोग के आयुक्त मेहर अली शाह ने पहली बार पाकिस्तान को मिल रहे कम पानी का आंकड़ा जारी किया है। मेहर अली के मुताबिक इस साल मई में करीब 16000 क्यूसेक कम पानी छोड़ा गया। यह सिर्फ चिनाब नदी का आंकड़ा है। सिंधु और अन्य नदियों के बारे में पाकिस्तान अभी डेटा इकट्ठा कर रहा है। मेहर अली का कहना है कि भारत के पानी रोकने से पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग मुसीबत हैं। मई 2025 के बाद से ही पानी के प्रवाह में कमी देखी जा रही है। हमें पहले लग रहा था कि यह ठीक हो जाएगा, लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं, वो काफी चौंकाने वाले हैं। अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान जल संधि को निलंबित कर दिया था।

चिनाब के पानी को भारत ने मोड़ा

सिंधु जल आयोग के आयुक्त का कहना है कि भारत ने चिनाब नदी के पानी को व्यास की तरफ मोड़ दिया, जिसके कारण पानी का प्रवाह कम हो गया है। इसके कारण पाकिस्तान के मराला पर मई 2025 में चिनाब नदी का प्रवाह बिना वर्षा के 78,276 क्यूसेक से घटकर 1,527 क्यूसेक रह गया। इसी तरह दिसंबर में यह और ज्यादा घटकर 870 क्यूसेक तक पहुंच गया। इस साल भी पानी रोकने के फैसले का असर देखा गया। मई 2026 में भी एक ही घटना के दौरान मराला के पास पानी का प्रवाह 21,887 से घटकर 5,689 क्यूसेक रह गया। अगर संख्या में कमी देखी जाए तो चिनाब से पाकिस्तान को करीब 16000 क्यूसेक कम पानी मिला। भारत के जल रोकने के फैसले से पहले पाकिस्तान को औसतन 46,00048,000 क्यूसेक पानी मिलता था।

पानी रोकने पाकिस्तान क्यों है परेशान?

मेहर अली शाह का कहना है कि भारत सिंधु, चिनाब और अन्य पश्चिम नदियों के पानियों को मोड़ना चाह रहा है। इसके लिए डैम और अन्य निर्माण कराए जा रहे हैं। अगर यह प्रयास भारत का सफल होता है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं मिल पाएगा। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी के लिए यह पानी काफी अहम है। इसके अलावा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी इन नदियों के पानी पर निर्भर है। नदियों के पानी से कृषि का काम संपन्न होता है, जिससे पाकिस्तान की एक चौथाई अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।

हर बैरल पर 5 डॉलर का डिस्काउंटइस फॉर्मूले से तेल बेच रहा ईरान

15 दिन में सऊदी-यूएई को पीछे छोड़ा

हिंदमाता नेटवर्क @ तेहरान

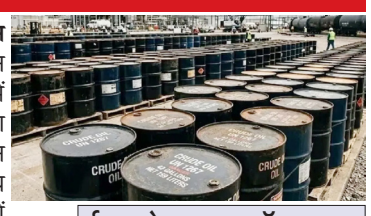

होर्मुज नाकाबंदी खत्म होने के बाद ईरान जमकर तेल बेच रहा है। पिछले 15 दिनों में ईरान ने 50 बैरल तेल बेच लिया है। रोजाना के हिसाब से देखा जाए तो ईरान प्रतिदिन 3 मिलियन बैरल से ज्यादा का तेल बेच रहा है। सऊदी, कतर और यूएई जैसे देशों के मुकाबले यह काफी ज्यादा है। सऊदी और यूएई जैसे देश फिलहाल 1-2 मिलियन बैरल तेल ही रोजाना बेच पा रहा है। टैंकर्स ट्रैकर्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से डील के बाद तेल बेचने की रफ्तार बढ़ा दी है। ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कालिबफ ने भी इसकी पुष्टि की है। कालिबफ के मुताबिक हम अब 20 प्रतिशत ज्यादा दाम पर तेल बेच रहे हैं। डील के तहत ईरान को अस्थाई तौर पर 60 दिनों के लिए तेल बेचने की छूट है। ईरान की कोशिश इन 60 दिनों में ज्यादा से ज्यादा तेल बेचने की है। ताकि उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

ईरान ने 3 अरब डॉलर का तेल बेचा

ईरान ने 15 दिनों के भीतर 3 अरब डॉलर यानी की 333 अरब रुपए का तेल बेच दिया है। ईरान ने अपना तेल चीनी करेंसी में बेचा है, ताकि उसे आने वाले वक्त में अमेरिका पर निर्भर न रहना पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अभी उन तेलों को बेच रहा है, जो पहले से टैंकर में अपलोड है। ईरान ने अधिकांश तेल खार्ग आइसलैंड के जरिए बेचा है। खार्ग होर्मुज के पास स्थित ईरान का एक अहम तेल टैंकर है।

हिंदमाता एंकर

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलेगा

केमिकल नहीं, फिर कैसे बचा रहा 4 महीने तक खामेनेई का शव? जनाजे से पहले सामने आया बड़ा सच

हिंदमाता नेटवर्क @ तेहरान

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को 9 जुलाई को पूरे इस्लामिक रीति रिवाज से दफन किया जाएगा। ईरान की सरकार ने उनके जनाजे में शामिल होने के लिए कई देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों को आमंत्रण भेजा है। भारत को भी इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलेगा। अली खामेनेई की मौत चार महीने पहले 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमले में हो गई थी। जिसके बाद से उनके शरीर हो किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाकर रखा गया था। इसी बीच अली खामेनेई के मृत शरीर को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जिसने इस्लामिक दुनिया में हलचल तेज कर दी है।

अब तक क्यों नहीं दफनाया गया

ईरान अपने सुप्रीम लीडर को पूरे सम्मान के साथ दफन करना चाहता था, जो जंग के माहौल में मुमकिन नहीं हो सकता था। ऐसे में ईरानी अधिकारियों ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उनके शरीर को सुरक्षित रखने का फैसला किया। अब जब जंग खत्म हो चुकी है तब खामेनेई की मौत के 132 दिनों बाद उन्हें दफनाने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच अफवाहें उठने लगी कि ईरान ने इस्लाम में केमिकल की मनाही के बावजूद खामेनेई के शरीर को केमिकल एम्बामिंग जरिए ममी बनाकर रखा है, ताकि उनके शरीर को नुकसान न हो।

नहीं की गई केमिकल एम्बामिंग

काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट डॉ। मोहम्मद उमर ने मीडिया से बात करते हुए कि सुप्रीम लीडर के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल किया है न की केमिकल एम्बामिंग की। उन्होंने कहा कि ईरान में इससे पहले भी शवों को कोल्ड स्टोरेज में कई महीनों तक रखने के बाद दफनाया गया है। यहां यह कोई नई बात नहीं है। उमर ने कहा कि, शिया समुदाय में शवों को कोल्ड स्टोरेज में रखने को लेकर कोई मनाही नहीं है। हालांकि, उमर ने इस दौरान एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि खामेनेई के शरीर के कुछ ही हिस्से सुरक्षित बचे हों। क्योंकि उनकी मौत मिलाइल हमले में हुई थी। अगर उनका शरीर सही सलामत होता तो सरकार उनके अंतिम संस्कार में इतना समय नहीं लगाती और न ही जनाजे के जुलूस को टालती।

कैसे हुई थी खामेनेई की मौत?

अली खामेनेई की मौत अमेरिका और इजरायल के हमले में हुई थी। इस हमले में उनके परिवार के कई लोगों की मौत हो गई थी। जिन्हें उसी समय दफना दिया गया था। हालांकि अली खामेनेई के शरीर को सुरक्षित रखा गया था। जिसे अब 9 जुलाई को दफनाया जाएगा।

बिजनेस वर्ल्ड

भारतीय शेयर बाजार से कब तक रुठे रहेंगे विदेशी निवेशक, 6 महीने में निकाले 2.7 लाख करोड़ रुपए

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

विदेशी निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालना लगातार जारी है। विदेशी निवेशकों ने जून में कुल 49,340 करोड़ रुपये घरेलू शेयर बाजार बाजार से निकाले। मुख्य रूप से वैश्विक जोखिम से बचने, विकसित बाजारों को प्राथमिकता और अमेरिकी बॉन्ड में तेजी तथा घरेलू बाजार में अधिक मूल्यांकन की वजह से बिकवाली की गयी। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि। के आंकड़ों के अनुसार, इस ताजा निकासी के साथ, 2026 में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) भारतीय इक्विटी बाजार से कुल 2.7 लाख करोड़ रुपये निकाल चुके है। यह पूरे वर्ष 2025 में निकाली गई 1.66 लाख करोड़ रुपये की राशि से कहीं अधिक है। आंकड़ों से पता चलता है कि एफपीआई फरवरी को छोड़कर 2026 के हर महीने में शुद्ध बिकवाल बने रहे। उन्होंने जनवरी में 35,962 करोड़ रुपये निकाले, जबकि फरवरी में शुद्ध लिवाल बनकर 22,615 करोड़ रुपये का निवेश किया, जो 17 महीनों में सबसे अधिक मासिक प्रवाह था। हालांकि, मार्च में विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड 1.17 लाख करोड़ रुपये निकाले। अप्रैल में शुद्ध रूप से 60,847 करोड़ रुपये और मई में 32,963 करोड़ रुपये की निकासी के साथ बिकवाली का दबाव जारी रहा। एफपीआई ने जून 49,340 करोड़ रुपये निकाले। मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के प्रमुख, प्रबंधक शोध हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि जून के पहले पखवाड़े में निकासी मुख्य रूप से वैश्विक जोखिम से बचने, विकसित बाजारों को प्राथमिकता, अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल अधिक होने और भारतीय शेयरों के मूल्यांकन को लेकर चिंताओं के कारण हुई। हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर सकारात्मक घटनाक्रम के बाद जून के दूसरे पखवाड़े में भू-राजनीतिक जोखिम कम हुए। इससे वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता कुछ कम होने और कच्चे तेल की कीमतों में सुधार में मदद मिली। इससे जोखिम धारणा में सुधार हुआ और ऊर्जा की कीमतों में अचानक उछाल को लेकर चिंताएं कम हुईं। इसके परिणामस्वरूप, महीने के आखिर में एफपीआई की बिकवाली की रफ्तार कम हुई।

भारत की इकोनॉमी ने फिर दिखाई ताकत, जून 2026 के आंकड़ों ने बढ़ाया भरोसा

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

दुनिया में चल रही उथल-पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था लगातार रफ्तार के रथ पर सवार है। सरकार की ओर से हाल ही में जारी किए गए आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि देश में विकास की रफ्तार बरकरार है। फिर चाहे वह जीडीपी में तेज बढ़ोतरी हो, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का विस्तार हो, रिकॉर्ड वाहन बिक्री हो या फिर मजबूत जीएसटी कलेक्शन और अच्छे निर्यात के आंकड़े हों। ये सभी आंकड़े संकेत देते हैं कि देश में मांग और निवेश लगातार बढ़ रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.7% की दर से बढ़ी। इसके साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा। वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही में विकास और तेज हुआ। इस दौरान वास्तविक जीडीपी 7.8% रही, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 7.0% थी। इस बढ़त में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, उपभोक्ता खर्च और निवेश का बड़ा योगदान रहा। जून 2026 में एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 54.2 रहा। यह लगातार 37वें महीने 50 अंक से ऊपर बना रहा, जो मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में लगातार विस्तार का संकेत है। सर्वे के अनुसार उत्पादन, नए ऑर्डर, रोजगार और खरीद गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हुई। इससे पता चलता है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है और कारोबारियों का भरोसा भी कायम है। एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स अप्रैल के 58.8 से बढ़कर मई 2026 में 59.8 पर पहुंच गया। यह नवंबर 2025 के बाद सबसे तेज विस्तार है। सर्वे के मुताबिक, बेहतर मांग, नए ग्राहकों के जुड़ने और नए कारोबार में बढ़ोतरी की वजह से यह सुधार देखने को मिला। वहीं, नए ऑर्डर पिछले छह महीनों में सबसे तेज गति से बढ़े। रोजगार में बढ़ोतरी और निर्यात मांग में सुधार से भी कारोबारी गतिविधियों को मजबूती मिली, जिससे भारत का सर्विस सेक्टर मजबूत बना हुआ है।

चीन के भरोसे नहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदकर खत्म होगी चुनौती

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

पश्चिम एशिया संकट ने भारत की ऊर्जा आयात पर निर्भरता की चुनौती को उजागर किया है। ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और महत्वपूर्ण कलपुर्जों के मामले में चीन पर निर्भरता घटाना बेहद जरूरी हो गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार तरुण कपूर ने ये बात कही है। उन्होंने उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा विकसित भारत के लिए भारत को इलेक्ट्रिक परिवहन केंद्र बनाना विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ-साथ महत्वपूर्ण कलपुर्जों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। तरुण कपूर के मुताबिक पश्चिम एशिया संकट के बाद यह और भी प्रासंगिक हो गया है। मैं कहूंगा कि अब हमारे देश के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना सबसे आवश्यक कार्य बन गया है, जिसे हम सभी को मिलकर पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि भारत का कच्चे तेल का आयात कम होता है, तो इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रुपये में भी सुधार होगा। संकट के दौरान शेयर बाजारों के हालात पर उन्होंने कहा, ऊर्जा के मामले में हम बाहरी परिस्थितियों के प्रति इतने अधिक संवेदनशील हो गए हैं कि यह हम सभी के लिए अब चिंता का गंभीर विषय है। इसलिए अब यह हम सभी के लिए एक मिशन बन गया है। कपूर ने कहा कि पेट्रोलियम का उपयोग पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कमी लाना भी बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने कहा, पेट्रोलियम की खपत में सिर्फ पांच प्रतिशत की कमी भी बड़ा अंतर पैदा कर सकती है और यह तभी संभव है, जब हम तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ें। उन्होंने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को धीरे-धीरे अपनाया गया है। दोपहिया और तिपहिया वाहनों के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन चारपहिया वाहनों के क्षेत्र में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। पेट्रोल की खपत सबसे ज्यादा दोपहिया वाहनों में होती है। देश में इस्तेमाल होने वाले कुल पेट्रोल का लगभग 60 प्रतिशत दोपहिया वाहन ही खर्च करते हैं। इसलिए इस श्रेणी में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव लाना बेहद महत्वपूर्ण है।

बजट को संभालेंगे एलआईसीऔर हिंदुस्तान जिंक! सरकार बेचने जा रही हिस्सेदारी

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

महंगे कच्चे तेल की वजह से सरकारी खजाने पर बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने विनिवेश की रफ्तार तेज कर दी है। सरकार आने वाले महीनों में देश की कई बड़ी सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। इस सूची में एलआईसी, हिंदुस्तान जिंक और कई सरकारी बैंक शामिल हैं। सरकार का मकसद हिस्सेदारी बिक्री के जरिए अतिरिक्त राजस्व जुटाकर वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल आठ सरकारी कंपनियों की पहचान की गई है, जिनमें हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अनुमान है कि सिर्फ एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने से सरकार को करीब 10,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। वहीं, हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी बिक्री से करीब 5,000 करोड़ रुपये जुटने की उम्मीद है। हिस्सेदारी बिक्री को सफल बनाने के लिए सरकार लगातार निवेश बैंकों के साथ बैठकें कर रही है। अधिकारियों और निवेश बैंकरों के बीच हर सप्ताह चर्चा हो रही है, जिसमें निवेशकों की मांग, शेयरों की कीमत और बिक्री का सही समय तय किया जा रहा है। इसके अलावा, भविष्य में अन्य सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी के लिए नए निवेश बैंकर भी नियुक्त किए जा रहे हैं। सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी बहुमत हिस्सेदारी बेचने की योजना पर भी दोबारा काम कर रही है। पिछली बार खरीदारों की कमजोर रुचि के कारण यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। अब सरकार रिजर्व प्राइस कम करने और पहले दौर में भाग लेने वाले निवेशकों से ही नए प्रस्ताव मंगाने पर विचार कर रही है। इससे इस बार सौदा पूरा होने की संभावना बढ़ सकती है। सरकार की इस योजना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। इस साल की पहली छमाही में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 29 अरब डॉलर की निकासी की है। इसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ा और निफ्टी-50 इंडेक्स में करीब 9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा, जियो प्लेटफॉर्म्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे बड़े आईपीओ भी निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं।

दैनिक ठाणे, शुक्रवार 3 जुलाई, 2026
हिंदमाता मिरर
पैनी नजर, पुख्ता खबर
GAME & GLAMOUR

विराट कोहली कर रहे पूर्व भारतीय कोच के साथ ट्रेनिंग

भारत के सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली की मैदान पर वापसी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह अनफिट होने के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में नहीं खेले, जिसमें भारत ने क्लीन स्वीप किया। कोहली के आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिताबी अभियान के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। कोहली अब 14 जुलाई से इंग्लैंड में एक्शन में नजर आएंगे, जहां भारत को तीन मैचों की वनडे सीरीज में भिड़ना है। कोहली ने आगामी सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर के साथ ट्रेनिंग की। कोहली का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा।

कोहली को इस शर्त पर चुना गया था

कोहली को फिटनेस मंजूरी मिलने की शर्त पर इंग्लैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया था। वह फिटनेस टेस्ट पास कर चुके हैं। टेस्ट और टी-20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके कोहली भारत के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कोहली के कंधे पर किट बैग लटका है और वह ट्रेनिंग ग्राउंड पर आए। इसके बाद, बांगर ने उनका स्वागत किया। बाद में दोनों ने बैठकर बातचीत भी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोहली ने हाल ही में अलीबाग और मुंबई में बांगर के साथ मिलकर ट्रेनिंग की, जिसमें उन्होंने सीरीज से पहले अपनी बैटिंग तकनीक को बेहतर करने पर खास ध्यान दिया। बीसीसीआई ने इंग्लैंड सीरीज के लिए शुभमन गिल की अगुवाई वाली वनडे टीम में कोई चौंकाने वाला बदलाव नहीं किया था, सिवाय इसके कि युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल को अफगानिस्तान सीरीज का हिस्सा रहने के बाद टीम से बाहर कर दिया गया। यशस्वी को कोहली के स्थान पर चुना गया था और उन्होंने चेन्नई में अंतिम वनडे में नाबाद शतक लगाया था। चयन समिति ने इस मामले में सामान्य प्रक्रिया अपनाई जिसमें चोट के कारण बाहर चल रहे पहली पसंद के क्रिकेटर की वापसी होने पर उसकी जगह चुने गए खिलाड़ी को बाहर होना पड़ता है। कोहली तीसरे नंबर पर वापसी करेंगे और गिल रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेज करने के लिए आराम देने के बाद टीम में वापस बुलाया गया। अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने भी वापसी की। उन्होंने युवा स्पिनर हर्ष दुबे की जगह ली। भारत बनाम इंग्लैंड तीन वनडे मैच एजबेस्टन (14 जुलाई), सोफिया गार्डन्स (16 जुलाई) और लॉर्ड्स (19 जुलाई) में आयोजित होंगे।

टेस्ट सीरीज का शेड्यूल
पहला टेस्ट: 15 से 19 अगस्त
दूसरा टेस्ट: 23 से 27 अगस्त

श्रीलंका से भिड़ेगी टीम इंडिया

भारत 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करेगा। ये दोनों मैच मौजूदा क्उउ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का हिस्सा होंगे। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाले में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा और आखिरी टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होंगे। यह सीरीज 2017 में श्रीलंका में 3-0 से शानदार जीत के बाद भारत का पहला टेस्ट दौरा है।

अफगानिस्तान को हराया

हाल ही में भारतीय टीम ने इकलौते टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को हराया था। श्रीलंका अभी वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज में है। टीम पहले मैच में बुरी तरह हारने के बाद वापसी की कोशिश करेगी।

भारत-श्रीलंका के लिए अहम सीरीज

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अहम पॉइंट्स दांव पर होने के कारण दोनों टीमों की नजर जीत पर होगी। फिलहाल भारत पॉइंट्स टेबल में पांचवें और श्रीलंका छठे स्थान पर है। ऐसे में आने वाली सीरीज दोनों टीमों के लिए हळउ फाइनल की दौड़ में आगे चल रही टीमों से अंतर कम करने का एक अहम मौका है।

भारत का पलड़ा भारी

- भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं।
- इस दौरान भारतीय टीम का पलड़ा काफी भारी नजर आता है।
- दोनों टीमों की भिड़ंत में भारत ने 22 टेस्ट मैच जीते हैं।
- वहीं श्रीलंका टीम को 7 मुकाबलों में ही जीत मिली है।
- 17 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं।
- श्रीलंका की धरती पर इन दोनों टीमों के बीच 24 टेस्ट मैच में आमना-सामना हुआ है।
- इस दौरान भारत को 9 और श्रीलंका को 7 मुकाबलों में सफलता मिली।
- 8 मैच ड्रॉ रहे। भारतीय टीम आखिरी बार 2017 में श्रीलंका में टेस्ट मैच खेली थी।
- 3 मैचों की इस सीरीज में भारत ने क्लीन स्वीप किया था।

शाहरुख ने विदेश में बनवाया खुद का क्रिकेट स्टेडियम

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने अपनी IPL फ्रेंचाइजी, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक अहम उपलब्धि की घोषणा की। KKR अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने वाला पहला ग्लोबल ब्रांड बन गया है, क्योंकि LA में नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड ने आधिकारिक तौर पर अपना पहला मेजर लीग मैच होस्ट किया है। इस मौके पर शाहरुख ने अपना सपना सच होने के बारे में बताया और आईसीसी चेयरमैन जय शाह तथा आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) संजोग गुप्ता का खासतौर पर धन्यवाद किया। बता दें कि पोमोना के फेयरफ्लेक्स में स्थित यह स्टेडियम 2028 के ओलंपिक से पहले मेजर लीग क्रिकेट मैचों की मेजबानी करेगा।

शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर किया एलान

दरअसल, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शाहरुख ने जय शाह, आईसीसी और संजोग ऋका उनके सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया। साथ ही लॉस एंजिल्स और इस कोशिश में शामिल टीम को भी उन्होंने खास मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि यह मैदान न केवल खेल की सुविधा है, बल्कि मनोरंजन, परिवारों और यादगार पलों के लिए भी एक जगह है, जिससे पता चलता है कि वे इसे क्रिकेट स्टेडियम के साथ-साथ संस्कृति और समुदाय के केंद्र के रूप में भी विकसित करना चाहते हैं। शाहरुख खान ने इस उपलब्धि को 'अकेले की जीत के बजाय सामूहिक प्रयास' बताया। पोस्ट में आगे कहा गया कि जयभाई का विशेष धन्यवाद, जो इस सफर में बहुत मददगार रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आईसीसी और उसके सीईओ संजोग गुप्ता का भी आभार जताया, जिन्होंने इस पहल को पूरा समर्थन दिया। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये एक सपने के रूप में शुरू हुआ था, वह आज हकीकत बन गया। लॉस एंजिलिस के नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में आप सभी का स्वागत है। उन्होंने साथ ही कहा कि यह स्टेडियम सिर्फ लॉस एंजिलिस के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस और पूरे नाइट राइडर्स परिवार के लिए है। उन्होंने अपने मशहूर संदेश 'बिलीव इन पर्पल एंड गोल्ड' के साथ फैंस का स्वागत किया और लॉस एंजिलिस नाइट राइडर्स के नए घर का हिस्सा बनने की अपील की।

नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड क्या है?

नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड लॉस एंजिलिस में तैयार किया गया नया क्रिकेट परिसर है, जिसका मकसद अमेरिका में क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव को मजबूत करना और खिलाड़ियों के साथ-साथ स्थानीय समुदाय को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ये मैदान मेजर लीग क्रिकेट में हिस्सा लेना वाली लॉस एंजिलिस नाइट राइडर्स टीम का नया घरेलू मैदान होगा।

कामाख्या देवी मंदिर पहुंचीं उर्फी जावेद

उर्फी जावेद अक्सर अपने अटपटे फैशन सेंस की वजह से ट्रोल होती हैं। कई बार वह इस वजह से कंट्रोवर्सी में भी घिर चुकी हैं। हाल ही में जब वह सादगी भरे और पारंपरिक पहनावे में कामाख्या देवी मंदिर पहुंचीं तो फैंस दंग रह गए। कई सोशल मीडिया यूजर्स को यकीन नहीं हुआ कि यह उर्फी जावेद हैं। उर्फी जावेद की सोशल मीडिया पोस्ट पर फैंस ने अजब-गजब किस्म के रिएक्शन दिए हैं।

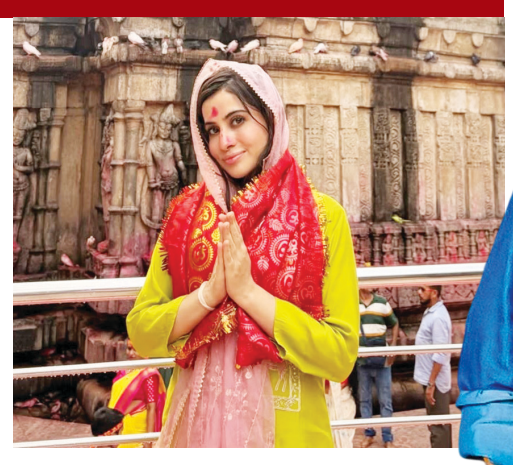

फैंस ने पूछ लिया बड़ा सवाल

उर्फी जावेद ने कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद कई तस्वीरें साझा कीं। इसमें वह सूट-सलवार पहने और सिर पर दुपट्टा लिए नजर आईं। साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा कि गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन किए। आगे उन्होंने फूल वाला इमोजी शेयर किया। यह फोटो देखकर कई फैंस ने कहा कि पहली बार अच्छी ड्रेस पहनी है। लेकिन एक सोशल मीडिया यूजर्स ने उर्फी से पूछा कि आप तो नास्तिक थीं ना!

उर्फी जावेद का करियर फ्रंट कैसा चल रहा है?

सोशल मीडिया पर इन दिनों क्रिएटिव ड्रेसेस पहने हुए उर्फी जावेद नजर आईं। साथ ही 'लॉकअप 2' के एपिसोड में भी बतौर गेस्ट वह पहुंची थीं। इससे पहले उर्फी जावेद रियलिटी शो 'स्पिट्सविला' का हिस्सा बनी थीं, बतौर होस्ट इस शो से जुड़ी थीं। वह कई और रियलिटी शो का हिस्सा रह चुकी हैं। अपनी ही लाइफ पर एक रियालिटी शो 'फॉलो कर लो यार' उर्फी ने किया।

फराह खान को मिला ऑस्कर्स का खास बुलावा

फिल्ममेकर फराह खान इन दिनों शो लॉकअप सीजन 2 होस्ट करती नजर आ रही हैं। इस बीच उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर खास जानकारी फैंस को दी है, जो कि हॉलीवुड से जुड़ी हुई है।

ऑस्कर्स ने मेंबरशिप के लिए किया इनवाइट

दरअसल, फराह खान को 'एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज' ने साल 2026 की मेंबरशिप के लिए इनवाइट किया है। इस खबर से खुश होकर फराह खान ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि वह इस सम्मानित ग्रुप का हिस्सा बनकर बहुत खुश और गर्व महसूस कर रही हैं।

529 लोगों को भेजा इनवाइट

हर साल एकेडमी दुनियाभर के कलाकारों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अपने मेंबर के रूप में शामिल करती है। इस साल कुल 529 लोगों को इनवाइट भेजा गया है, जिसमें फराह खान भी शामिल हैं। अब वह ऑस्कर अवॉर्ड्स के वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा बन सकेंगी। फराह खान के अलावा इस लिस्ट में कई और भारतीय नाम भी शामिल हैं। इनमें मशहूर फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज का नाम है, जो 'मकबूल', 'ओमकारा' और 'हैदर' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।

दीपा भाटिया और एका लखानी का नाम शामिल

इसके साथ ही दिग्गज एडिटर ए. श्रीकर प्रसाद और दीपा भाटिया को भी इनवाइट मिला है। दीपा भाटिया ने 45 साल से ज्यादा लंबे करियर में 'आरआरआर', 'दिल चाहता है', 'साथिया', 'तारे जमीन पर', 'रॉक ऑन!!', 'माय नेम इज खान' और 'काय पो छे' जैसी फिल्मों में काम किया है। इस लिस्ट में कॉस्ट्यूम डिजाइनर एका लखानी, कास्टिंग डायरेक्टर दिलीप शंकर और डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर शालिनी कांतैया का नाम भी शामिल है।

एनीमेशन कैटेगरी में अवनीत कौर को भेजा इनवाइट

इसके अलावा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ और प्रोफेशनल्स को भी इनवाइट मिला है। इनमें एनीमेशन कैटेगरी में अवनीत कौर, प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी में राजेश रामचंद्रन, और विजुअल इफेक्ट्स में बेकी ग्राहम और जय मेहता शामिल हैं। इस इनवाइट को स्वीकार करने के बाद ये सभी लोग दुनिया के करीब 11,000 से ज्यादा एकेडमी मेंबर्स का हिस्सा बन जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें ऑस्कर अवॉर्ड्स में वोट देने का अधिकार भी मिलेगा, जिससे वे नॉमिनेशन और विनर्स चुनने में हिस्सा ले सकेंगे।

शरवरी वाघ का वर्कआउट

शरवरी वाघ अपनी अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' को लेकर चर्चा में हैं। यह फिल्म 3 जुलाई को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में आलिया भट्ट और वह एक्शन रोल में नजर आई हैं। फिल्म की रिलीज से पहले शरवरी वाघ ने सोशल मीडिया पर अपनी वर्कआउट करते हुए तस्वीरें शेयर की हैं।

शरवरी की पोस्ट में क्या है?

शरवरी वाघ ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें देखा जा सकता है कि वह डंबल लिए हुए नजर आ रही हैं। कई दूसरी तस्वीरों में वह व्यायाम करती हुई दिख रही हैं।

उत्साहित हुईं शरवरी वाघ

शरवरी वाघ ने भूरे रंग की ड्रेस में कई पोज दिए हैं। तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि बड़े दिन से पहले, हफ्ते के बीच में मोटिवेशन! अल्फा की रिलीज में दो दिन बाकी हैं।

यूजर्स को पसंद आईं तस्वीरें

शरवरी की तस्वीरों पर कई फैंस ने कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा कि बहुत ही सुडौल बॉडी। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि ईमानदारी से कहूं तो मैं आपसे प्यार करती हूं। एक और यूजर ने लिखा कि आप बहुत मजबूत हैं। एक और यूजर ने लिखा कि यह आसान काम नहीं है। बहुत कठिन काम है।

कब रिलीज होगी 'अल्फा'?

ख्याल रहे कि फिल्म 'अल्फा' 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में आलिया के अलावा शरवरी वाघ, अनिल कपूर और बॉबी देओल अहम किरदारों में हैं। 'अल्फा' यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म है।

राशा थडानी ने जरूरतमंद की मदद के लिए बढ़ाया हाथ

रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने अपने करियर की शुरुआत पिछले साल 'आजाद' से की थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता नहीं मिली। लेकिन राशा के पास ऑफर्स की कमी नहीं है। अपनी फिल्मों के अलावा वह अपने व्यवहार को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह बारिश के मौसम में मुंबई के एक मंदिर में पहुंचीं। इस दौरान एक बूढ़ी महिला उनसे मदद मांगती दिखे, राशा ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। राशा की इस दरियादिली को फैंस अब खूब सराह रहे हैं।

जरूरतमंद महिला को दिए 500 रुपए

वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि राशा मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद बाहर निकलती हैं। अचानक सामने एक बूढ़ी महिला पड़ जाती हैं। वह राशा से कुछ मांगती हैं। राशा पर्स से 500 का नोट निकालकर उस महिला को देती है। बूढ़ी महिला राशा को खूब आशीष देती है। वीडियो में राशा की दरियादिली को देखकर फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं।

करियर फ्रंट पर क्या कर रही हैं राशा?

राशा थडानी की जल्द ही एक बॉलीवुड फिल्म रिलीज होगी। सौरभ गुप्ता निर्देशित 'लईकी लईका' में राशा और अभय लीड रोल में नजर आएंगे। दोनों पहली बार किसी फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। यह 2026 की गर्मियों में रिलीज होगी। इसके अलावा राशा एक साउथ फिल्म भी कर रही हैं।

दोबारा दूल्हा बने अशोक सराफ

बॉलीवुड के फेमस एक्टर अशोक सराफ इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में चल रहे हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि 78 की उम्र में उन्होंने फिर से शादी कर ली है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी संग तस्वीरें शेयर की है और जीवन भर एक-दूसरे का साथ निभाने की कसमें खाई हैं। फोटो देखने के बाद हर कोई सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाई दे रहा है। मराठी सिनेमा में अशोक सराफ का बहुत नाम है। हर रोल में अशोक सराफ ने अपनी एक्टिंग के जरिए इंडस्ट्री में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। अब उन्होंने अपनी पत्नी निवेदिता सराफ संग दोबारा शादी रचा के प्यार की मिसाल कायम कर दी है। बता दें कि दोनों ने 1990 में शादी की थी और अब 37 वर्ष बाद अपनी एनिवर्सरी वाले दिन दोनों ने फिर से शादी की रस्में निभाई हैं।

78 की उम्र में दोबारा दूल्हा बने अशोक सराफ

इस मौके पर अशोक सराफ ने तस्वीरें शेयर की हैं और बहुत प्यारा कैप्शन भी लिखा है कि 37 साल बाद भी, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरा दिल वैसे ही मुस्कुराता है। मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरी ताकत और हमेशा के लिए मेरे प्यार बने रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शादी की सालगिरह मुबारक हो।

अशोक सराफ की लाइफ

1990 ने अशोक ने निवेदिता संग गोवा के एक मंदिर में फेरे लिए थे। दोनों का एक बेटा है, जिसका नाम अनिकेत सराफ हैं।

कौन है अशोक की पत्नी निवेदिता सराफ ?

एक्टर अशोक को तो हर कोई जानता है लेकिन आपको बता दें कि उनकी बीवी की कोई आम इंसान नहीं हैं। निवेदिता जोशी मराठी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। 10 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने करियर की शुरूआत कर दी थी। इनके पिता गजानन जोशी का भी मराठी सिनेमा में बहुत नाम है।

श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक तो जड़ा

श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 मैच में 130 से अधिक की स्ट्राइक रेट से अर्धशतक तो जड़ा लेकिन वे सूर्यकुमार यादव और केएल राहुल से एक खास रिकॉर्ड में पीछे रह गए। यहां तक कि रोहित शर्मा और सुरेश रैना से भी पीछे चले गए। दरअसल, अय्यर का आयरलैंड सीरीज में बल्ला नहीं चला लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। बतौर कप्तान तीसरी पारी में उन्होंने यह अर्धशतक जड़ा। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों में 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 68 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 144.68 रहा। टी-20 की कप्तानी संभालने के बाद श्रेयस अय्यर ने तीसरी पारी में अर्धशतक लगाया है, जबकि सूर्यकुमार यादव और केएल राहुल ने अपने पहले ही मुकाबले में फिफ्टी जड़कर कमाल कर दिया था। सूर्यकुमार यादव ने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नवंबर 2023 में कप्तानी डेब्यू करते हुए 43 गेंदों में 80 रन बना दिए थे।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक नरेश पी. बजाज द्वारा बैरक नंबर 887/27 सेक्शन 18, उल्हासनगर -421 003, जिला ठाणे से प्रकाशित व सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, आमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट, सोनवाला क्रॉस रोड -2, जवाहरनगर के पास, फाटक पुल, गोरेगांव, मुंबई -63, (महाराष्ट्र) से मुद्रित।
दूरध्वनि: 0251- 3238100, **कार्यकारी संपादक:** पंजू बजाज (पी. आर. बी. एक्ट के तहत कंटेट चयन के लिए जिम्मेदार) न्याय क्षेत्र ठाणे जिला। **hindmatamirror1@gmail.com** RNI. NO. MAHHIN/2011/43060 **स्थानीय संपादक:** शिवप्रताप